RNI No. : TNHIN/2013/52520 ▪ वर्ष - 14 ▪ अंक - 2 ▪ पृष्ठ - 8 ▪ रु. 5/- चेन्नई » शुक्रवार » 24-07-2026 ▪ www.dakshinbharat.com ▪ Email : chennai@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

4 सुमेरपुर के राजकीय महाविद्यालय में कैबिनेट मंत्री कुमावत ने किया
6 विश्व में भारत के खिलाफ नैरेटिव गढ़ता बीबीसी
7 छात्रों के समर्थन में उतरीं आलिया भट्ट

फर्स्ट टेक

सिक्किम सुरंग हादसा : सभी 25 श्रमिकों के शव बरामद

नामची/भाषा। सिक्किम के नामची जिले में एनएचपीसी की निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजना की सुरंग से सभी 25 श्रमिकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। एनएचपीसी की तीस्ता चरण-6 जलविद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग सोमवार अपराह्न एक बजे के कुछ देर बाद संदिग्ध रूप से मीथेन गैस के कारण हुए विस्फोट के बाद ढह गई थी और उस समय सुरंग में 25 श्रमिक मौजूद थे। 'ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड' के बचाव दल के सदस्य के. के. रॉय ने संवाददाताओं को बताया कि लगातार 72 घंटे तक चले तलाशी अभियान के बाद सभी शव बरामद कर लिए गए हैं। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा, ''सिक्किम सरकार, जिला प्रशासन और सभी संबंधित एजेंसियां स्थिति पर लगातार नजर रख रही हैं तथा प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध करा रही हैं।''

सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द की

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने 2025 में हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करने की आरोपी सोनम रघुवंशी को दी गई जमानत बृहस्पतिवार को रद्द कर दी और तीन सप्ताह के भीतर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ ने सोनम को जमानत दिए जाने के खिलाफ मेघालय सरकार की याचिका स्वीकार कर ली। पीठ ने कहा, प्रतिवादी (सोनम) ने अपनी गिरफ्तारी के कारणों पर संतुष्टि जताई। दस्तावेज वास्तव में उसे दिए गए थे। इसलिए, हम गिरफ्तारी की वैधता के मुद्दे पर नहीं जाना चाहते। इतना कहना काफी है कि ''दोनों अदालतों ने इस अदालत के फैसले के आधार पर जमानत देकर गलती की है।''

न्यायालय में 96,000 से अधिक मामले लंबित : मेघवाल

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा को बताया कि उच्चतम न्यायालय में 96,000 से अधिक मामले लंबित हैं जिनमें से 10,000 से अधिक मामले एक दशक से अधिक समय से निपटान की प्रतीक्षा में हैं। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय, 25 उच्च न्यायालयों और जिला एवं अधीनस्थ अदालतों में कुल मिलाकर 5.64 करोड़ मामले लंबित हैं। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में 80,660 मामले 30 साल से अधिक समय से लंबित हैं।

सूर्यास्त 24-07-2026	सूर्योदय 25-07-2026
6:38 बजे	5:54 बजे

BSE	NSE
76,391.39	23,869.60
(-363.660)	(-126.66)

सोना	चांदी
15,056 रु.	245,000 रु.
(24 कैरेट) प्रति ग्राम	प्रति किलो

संसद में चौथे दिन भी गतिरोध कायम

विपक्ष प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा

लोकसभा की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों को उठाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनसे प्रश्नकाल चलने देने की अपील करते हुए आश्वासन दिया कि प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद वह सदस्यों को उनकी बात रखने का अवसर देंगे।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बृहस्पतिवार को भी संसद के दोनों सदनों में गतिरोध कायम रहा और लोकसभा जहां दो बार के वहीं राज्यसभा तीन बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में चर्चा के लिए पूर्व शर्त लगाकर इससे भाग रहा है। उसने कहा कि सरकार तत्काल चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बिना देरी के चर्चा शुरू करनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि विपक्ष से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि वह चर्चा में भाग ले।

लोकसभा की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों को उठाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनसे प्रश्नकाल चलने देने की अपील करते हुए आश्वासन दिया कि प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद वह सदस्यों को उनकी बात रखने का अवसर देंगे। लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा और बिरला ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद बैठक 12 बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा, हमने कल भी अपील की थी और आज फिर से सदन से अपील कर रहे हैं कि नीट पेपर लीक मामले में चर्चा बिना विलंब के शुरू होनी चाहिए। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आसन के समीप हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से कहा कि सरकार चर्चा चाहती है और सदन की कार्यवाही बाधित करना उचित नहीं है। हंगामा थमते नहीं देख उन्होंने करीब 10 मिनट बाद बैठक दो बजे तक स्थगित कर दी। दो बजे बैठक फिर शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने विपक्ष से नियम 377 के तहत सदस्यों को उनके मुद्दे उठाने देने की अपील की, लेकिन विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। सैकिया ने करीब तीन मिनट बाद ही कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी।

प्रश्नपत्र लीक मामले पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान उकसाने वाला : खरगे

नई दिल्ली/भाषा। राज्यसभा में बृहस्पतिवार को नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रश्नपत्र लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आज दिये गये बयान को ''उकसाने वाला'' करार दिया और कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, विपक्ष संसद में इस विषय पर चर्चा में भाग नहीं लेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर आज दिये गये बयान में कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र लीक के मामलों में शामिल लोगों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए सरकार ने त्वरित अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है। उच्च सदन में गुरुवार को हंगामे के बीच सभापति सी पी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष खरगे को बोलने का अवसर दिया तो उन्होंने कहा, ''आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया है, वह उकसाने वाला बयान है।'' शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, इसके बाद विपक्ष चर्चा करने के लिए तैयार है।

राम मंदिर का विरोध करने वालों को उपदेश देते देखना हास्यास्पद है : आदित्यनाथ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गोरखपुर/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी (सपा) की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह हास्यास्पद है कि जो लोग राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ अदालत गए थे, वे अब आस्था पर उपदेश दे रहे हैं। आदित्यनाथ ने यह बात अपने निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर (शहरी क्षेत्र) में 995 करोड़ रुपये से अधिक की 14 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के बाद कही। योगी आदित्यनाथ उप्र विधानसभा में गोरखपुर (शहरी क्षेत्र) सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा, ''वर्ष 2017 से पहले दंगे आम बात थी और अराजकता चरम पर थी। जरा याद कीजिए कि होली, विजयादशमी, दुर्गा पूजा और राम नवमी के दौरान कैसे दंगे भड़क उठते थे। वे जन्माष्टमी का जश्न या कांवड़ यात्रा नहीं होने देते थे।'' भाजपा नेता ने कहा, ''संक्षेप में कहें तो, जो लोग उस समय आस्था के मामलों को लेकर हमला किया करते थे, अब वही खुद को उस आस्था के सबसे बड़े चैंपियन के रूप में पेश करने में जुट गए हैं।''

आदित्यनाथ ने कहा, ''जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के रास्ते में बाधाएं पैदा कीं, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान भगवान राम के भक्तों पर गोलियां चलवाईं, जिन्होंने मंदिर का विरोध करने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपने वकील तैनात किए, वही लोग आज आस्था के बारे में बोल रहे हैं।

ये वही लोग हैं जो आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, किसानों का हक छीनते थे और व्यापारियों और बेटियों के लिए सुरक्षा का संकट पैदा करते थे। आज जब वे इन मुद्दों पर बड़े-बड़े उपदेश देते हैं, तो हास्यास्पद लगता है।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि दस साल पहले, जब वे राज्य में सत्ता में नहीं आए थे, तब लोग माफिया और मच्छरों की वजह से गोरखपुर आने से डरते थे।

कांग्रेस और 'इंडि' गठबंधन के सांसदों ने पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि दी

> लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने गांधी स्मृति जा रही बस में खड़े होकर एक वीडियो में कहा, जाहिर है, वे डरे हुए हैं। हम सभी सांसदों को लगा कि अगर छात्र सड़कों पर हैं, तो हमें भी सड़कों पर होना चाहिए।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस और 'इंडि' गठबंधन में शामिल दलों के कई नेताओं ने उन सभी छात्रों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने पेपर लीक के कारण अपनी जान दे दी। नेताओं ने कहा कि वे प्रदर्शन कर रहे छात्रों और उनकी मांगों के साथ मजबूती से खड़े हैं। इससे पहले, कांग्रेस और 'इंडि' गठबंधन में शामिल कई दलों के नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 5, सुनहरी बाग रोड स्थित आवास पर इकट्ठा हुए और प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगों के लिए अपना पूर्ण समर्थन दोहराया। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसद बस में सवार होकर गांधी स्मृति' गये। वहां पहुंचकर, गांधी और विपक्ष के सांसदों ने हाथ जोड़कर दिवंगत छात्रों को श्रद्धांजलि दी और बाद में राष्ट्रगान गाया।

गांधी अपने साथ संविधान की एक छोटी प्रति लिये हुए थे, जबकि विपक्षी सांसद महुआ माझी और महुआ मोइत्रा राष्ट्रीय ध्वज पकड़े हुए दिखीं। कुछ सांसदों ने 'गांधी स्मृति' में अपने मोबाइल फोन की टॉर्च भी जलाई। पुलिस ने सुनहरी बाग रोड पर बैरिकेड लगा दिए थे ताकि कांग्रेस और इसकी युवा इकाई के कार्यकर्ताओं को तीस जनवरी मार्ग की ओर जाने से रोका जा सके, जहां कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेता जा रहे थे। हालांकि, बाद में पुलिस ने बैरिकेड हटा दिए और गांधी और अन्य सांसदों को आगे बढ़ने की इजाजत दे दी। जब वे सुनहरी बाग रोड के आखिर में और अमित शाह के घर के पास पहुंचे, तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया और कहा कि उन्हें वहां इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है क्योंकि बीएनएस की धारा 163 लागू है, जिसके तहत उस इलाके में पांच या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। बाद में पुलिस ने गांधी और अन्य लोगों को तीस जनवरी मार्ग की ओर जाने की इजाजत दे दी।

राहुल गांधी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि कोई भी उन्हें भारत के छात्रों के साथ खड़े होने से नहीं रोक सकता। राहुल गांधी ने कहा, छात्रों के साथ एकजुटता दिखाते हुए, हम विपक्षी सांसदों को इंडिया गेट ले जाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर, हम उन्हें तीस जनवरी मार्ग, यानी गांधी जी की हत्या वाली जगह ले जाना चाहते थे। उन्होंने कहा, ''अब, उन्होंने हमारे सामने बस खड़ी कर दी है ताकि हम वहां न पहुंच सकें। उन्होंने हमें आगे बढ़ने से रोकने के लिए यह बस और बैरिकेड लगाए हैं। वे यह नाटक कर रहे हैं।''

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने गांधी स्मृति जा रही बस में खड़े होकर एक वीडियो में कहा, ''जाहिर है, वे डरे हुए हैं। हम सभी सांसदों को लगा कि अगर छात्र सड़कों पर हैं, तो हमें भी सड़कों पर होना चाहिए।'

पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की वजह से गाड़ी में खराबी की कोई समस्या सामने नहीं आई : गडकरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने बृहस्पतिवार को लोकसभा को बताया कि 'सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफेक्चरर्स' (सायम) से मिली जानकारी के अनुसार, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की वजह से बड़े पैमाने पर इंजन खराब होने या गाड़ी के बंद हो जाने की कोई समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह बात कही। उन्होंने कहा, ''इंजन के काम करने, गाड़ी के माइलेज से जुड़ी कुछ चिंताएं अधिकतर सार्वजनिक टिप्पणियों और सोशल मीडिया पर चर्चा के जरिए सामने आ रही हैं।''

गडकरी ने कहा कि ई15+ ब्लेंडेड पेट्रोल साढ़े तीन साल से ज्यादा समय से और ई19-ई20 मिश्रित ईंधन ढाई साल से ज्यादा समय से देश भर में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। गडकरी ने कहा कि सरकार ने, हितधारकों के साथ सलाह-मशविरा करके, परीक्षण करके और इथेनॉल मिश्रण बढ़ाने के हर चरण पर विशेषज्ञ एजेंसियों से अधिमान्य कराके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय में, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम शुरू किया है। मंत्री ने बताया कि ईबीपी कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से, वैज्ञानिक रूप से मान्यता प्रदान करते हुए और परामर्श करने के तरीके से लागू किया गया है।

उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल दुनिया भर में एक सदी से भी ज्यादा समय से किया जा रहा है, जिसमें ब्राजील जैसे देश दशकों से अधिक इथेनॉल मिश्रित ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं।

आतंकी कृत्यों के नतीजे भुगतने होंगे : जयशंकर

मनीला/भाषा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं की नीति पर अडिग रहते हुए चेतावनी दी कि आतंकी कृत्यों के नतीजे भुगतने होंगे। जयशंकर फिलीपीन की राजधानी मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ)की मंत्री-स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने इसी के साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस मंच के महत्व को रेखांकित किया। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अपने भाषण की मुख्य बातें बताते हुए कहा, आतंकवाद के कतई बर्दाश्त नहीं की नीति होनी चाहिए। साथ ही, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे। जयशंकर ने आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा, भारत, एडीएमएम प्लस(आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस) में मलेशिया के साथ मिलकर विशेषज्ञ कार्य समूह की सह-अध्यक्षता करता है और सर्वोत्तम तौर-तरीकों का संकलन तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। जयशंकर ने रेखांकित किया कि समुद्री जहाजों और आम लोगों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचों पर हमले अस्वीकार्य' हैं।

मिशन मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

सकते में लोकतंत्र

लोकतंत्र हो गया है मंथर,
तानाशाही के हैं मंज़र।
मासूमों पर चलते हंटर,
इनमें गोरों में क्या अंतर।
सब खुद को खुद कहे धुरंधर,
कोलाहल संसद के अंदर।
जो भी जीता वही सिकंदर।
सकते में है जंतर-मंतर।।

गंगा के निकट अवैध निर्माण चिंता का विषय, छह सप्ताह में हटाए जाएं सभी ढांचे : न्यायालय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने गंगा नदी के किनारे हो रहे अवैध निर्माणों को गंभीर चिंता का विषय मानते हुए बिहार सरकार को पटना में नदी के किनारे नौजर घाट से नूरपुर घाट तक सभी अवैध ढांचों व अतिक्रमणों को छह सप्ताह के अंदर हटाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि पहले दिए गए आदेशों के बावजूद अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

पीठ ने कहा, हमें बताया गया है कि अब तक अतिक्रमण हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। हम यह सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार को छह सप्ताह का समय देते हैं कि पटना में नौजर घाट से नूरपुर घाट के बीच सभी अवैध ढांचे, निर्माण और अतिक्रमण हटा दिए गए हैं। पीठ ने सक्षम प्राधिकारी को इस संबंध में सुनवाई की अगली तारीख तक हलफनामे के रूप में कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अवैध निर्माणों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश करने के लिए और समय मांगा। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने अभी तक जरूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। इस पर उच्चतम न्यायालय ने कहा, सभी राज्यों को केंद्र सरकार को आवश्यक जानकारी देने का अंतिम अवसर दिया जाता है।

संबोधन

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों और वकीलों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की निंदा के लिए गुरुवार को उच्चतम न्यायालय परिसर में आयोजित वकीलों के जमावड़े के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने मीडिया को संबोधित किया।

तूलिका, व्यंग्य और विरोध के रंगों का कैनवास बना जंतर-मंतर, छात्रों ने कला को बनाया आंदोलन की आवाज

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रश्नपत्र लीक' मामले में जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने अपनी रचनात्मकता को आंदोलन का माध्यम बना दिया है।

उन्होंने रंग-तूलिका, चित्रों, व्यंग्य, पोस्टरों और लोकप्रिय संस्कृति के प्रतीकों के जरिए विरोध दर्ज कराते हुए प्रदर्शन स्थल को खुली कला दीर्घा (ओपन-एयर गैलरी) में बदल दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के 'संसद चलो' मार्च को पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद भी जंतर-मंतर पर छात्रों का धरना जारी है। भाषणों और नारेबाजी के बीच प्रदर्शन स्थल पर हाथ से बनाए गए चित्र, अनोखी वेशभूषा, काव्यात्मक तख्तियां, कार्टून, व्यंग्यचित्र और इंटरनेट पर प्रचलित हास्य चित्र (मीम) नजर आए। इन माध्यमों से छात्र अपनी मांगों को रचनात्मक ढंग से सामने रख रहे हैं।

यहां एक सैनिटरी पैड पर हाथ से लिखा संदेश नजर आता है, ''...यह पैड भी लीक नहीं होता''। यह कथित प्रश्नपत्र लीक पर व्यंग्य था। प्रदर्शन स्थल पर महात्मा गांधी के तीन बंदरों की तर्ज पर बनाई गई एक कलाकृति रखी है। इसमें एक बंदर की आंखों पर पट्टी बंधी थी, दूसरे के मुंह पर ताला लगा था और तीसरा अपने कानों में तेल डालता हुआ दिखाया गया था। इनके साथ लिखे संदेश थे- ''पट्टी चोट पर लगाओ, आंखों पर नहीं'', ''ताला दरवाजे पर लगाओ, मुंह पर नहीं'' और ''तेल कानों में नहीं, बालों में डालो''। इन संदेशों के जरिए छात्रों ने अधिकारियों से उनकी समस्याओं की अनदेखी नहीं करने, आवाज नहीं दबाने और शिकायतों पर ध्यान देने की अपील की। इतिहास और क्रांति की झलक भी यहां दिखती है। हाथ से बनाए गए डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्रों के साथ क्यूबा के क्रांतिकारी चे ग्वेरा के पोस्टर भी यहां हैं।

पुनर्चक्रित (रीसाइकिल किए गए) कागज और रोजमर्रा की वस्तुओं से तैयार की गई कलाकृतियों ने प्रदर्शन को युवाओं की ऊर्जा और रचनात्मकता से भर दिया। कुछ प्रदर्शनकारी महात्मा गांधी का वेश धारण कर पहुंचे। इनमें एक चित्रण में गांधी की आंखों से खून जैसे आंसू बहते हुए दिखाए गए थे। लोकप्रिय फिल्मों और संस्कृति का भी प्रदर्शन में व्यापक इस्तेमाल किया गया। एक पोस्टर पर फिल्म 'गोलमाल 3' के प्रसिद्ध संवाद को बदलकर लिखा गया था, ''जल्दी इस्तीफा दो, सुबह पनवेल जाना है''। वहीं एक अन्य पोस्टर में फिल्म 'तू झूठी मैं मक्कार' के शीर्षक का इस्तेमाल दो राजनीतिक नेताओं के व्यंग्यचित्रों के साथ किया गया था।

एक अन्य पोस्टर में भारत के नक्शे को चाय में डुबोए जा रहे बिस्कुट के रूप में दिखाया गया था। प्रदर्शनकारी हार्दिक ने कहा, मैं दिखाना चाहता था कि देश के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। इस पोस्टर को बनाने में मुझे दो दिन लगे। इसे मैं सोमवार के मार्च में भी लेकर गया था और आज फिर यहां लाया हूं, ताकि अधिक लोग इसका संदेश देख सकें।

प्रदर्शनकारी शिवांगी ने जापानी मंगा और एनीमे श्रृंखला 'वन पीस' के 'स्ट्रॉ हैट पाइरेट' के प्रतीक वाले दुपट्टे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह एक चेतावनी का संकेत है। इसके जरिए हम कहना चाहते हैं कि कुछ बहुत गलत हो रहा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रदर्शन में हास्य का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया है। एक तख्ती पर लिखा है, ''स्थिति इतनी खराब है कि अंतर्मुखी लोग भी यहां आ गए हैं'', जबकि एक अन्य पोस्टर में आंदोलन का समर्थन करता हुआ कार्टून कॉकरोच बनाया गया था। मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को कॉजपा के आह्वान पर हजारों लोगों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद की ओर मार्च किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था।

दक्षिण गुजरात में मूसलाधार बारिश

जनजीवन अस्त-व्यस्त; हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गये

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अहमदाबाद/भाषा। दक्षिण गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वलसाड जिले के उमरगांव तालुका में बृहस्पतिवार सुबह तक 16 घंटे के दौरान 1,100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद प्रशासन ने निचले इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।

अधिकारियों ने बताया कि लगातार बारिश के कारण सूरत जिले में नदियां और अन्य जलाशय उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। अहमदाबाद में केवल दो घंटे में 66 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे कई सड़कों पर जलभराव हो गया और यातायात प्रभावित हुआ। दक्षिण गुजरात में भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए मुंबई जाने वाली कई रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया या उनका मार्ग छोटा कर दिया गया। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार, बुधवार सुबह छह बजे से बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे तक वलसाड जिले का उमरगांव तालुका 1,100 मिलीमीटर से अधिक बारिश के साथ सबसे अधिक प्रभावित रहा। इस दौरान वलसाड जिले के कई अन्य तालुकों में भी 600 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। अधिकारियों ने बताया कि औरंगा, पार और दमनगंगा जैसी नदियों के उफान पर आने से वलसाड जिले के निचले इलाकों में व्यापक जलभराव हो गया, जिसके कारण हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं, सूरत शहर के निचले इलाकों में रहने वाले 2,200 से अधिक लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया। तापी, डांग, सूरत और नवसारी जिले भी भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण सामान्य जनजीवन बाधित हुआ और प्रशासन ने बचाव एवं राहत अभियान तेज कर दिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बृहस्पतिवार और शुक्रवार के लिए वलसाड, नवसारी, डांग, सूरत और तापी जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट' जारी किया है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बचाव और राहत कार्यों की निगरानी के लिए विभिन्न मंत्रियों को प्रभावित जिलों में भेजा है। सूरत में अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने नौकाओं की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।

संसद के बाहर विपक्षी और राजग सांसद आमने-सामने, एक दूसरे के खिलाफ लगाए नारे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों में बृहस्पतिवार को भी व्यवधान रहने का संकेत देते हुए विपक्ष और सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सांसदों ने संसद परिसर के बाहर एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की।

संसद के मकर द्वार के बाहर दोनों पक्षों के सांसद बड़ी संख्या में एकत्र हुए और एक-दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। राजग सांसदों ने प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने ''शर्म करो, शर्म करो'' और ''वंदे मातरम'' जैसे नारे लगाए। वहीं, विपक्षी 'इंडि' गठबंधन के सांसदों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए ''इस्तीफा दो'', ''गद्दी छोड़ो'' और शर्म करो'' जैसे नारे लगाए। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाद्रा तथा कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के कई सांसदों ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग वाला एक बड़ा बैनर लेकर प्रदर्शन किया।

बाद में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और 'इंडि' गठबंधन के अन्य नेता भी संसद के बाहर प्रदर्शन में शामिल हुए। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले राहुल गांधी, अखिलेश यादव और 'इंडि' गठबंधन के अन्य नेताओं ने अपनी विरोध की रणनीति को लेकर बैठक भी की।

अन्ना हजारे ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के समर्थन में 'मौन आंदोलन' किया

अहिल्यानगर/भाषा। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के समर्थन में बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में दो घंटे का 'मौन आंदोलन' किया। अन्ना ने अहिल्यानगर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास पूर्वाह्न 11 बजे अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया और अपराह्न एक बजे इसे समाप्त किया। इसके बाद वह इसी जिले में स्थित अपने गांव रालेगण सिद्धि के लिए रवाना हो गए। हजारे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बुधवार को पत्र लिखकर कहा था, हिंसा और पुलिस कार्रवाई की खबरें बेहद पीड़ादायक हैं। उन्होंने पत्र में कहा था कि ''प्रदर्शनकारियों के असंतोष को कानून-व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं, बल्कि समाज की पीड़ा और अपेक्षाओं के रूप में देखा जाना चाहिए।''

हजारे ने लिखा था कि यदि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने को कहा जाता है तो इससे सरकार नहीं गिरेगी, बल्कि उसकी कार्यप्रणाली अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनेगी। उन्होंने सरकार से प्रदर्शनकारियों की बात धैर्यपूर्वक सुनने, विश्वास का माहौल बनाने और सकारात्मक संवाद के जरिये समाधान तलाशने का अनुरोध किया।

रथ यात्रा अनुष्ठानों के लिए गुंडिचा मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पुरी/भाषा। ओडिशा के पुरी स्थित गुंडिचा मंदिर में बृहस्पतिवार शाम छह बजे से श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद रहेगा। यह भगवान जगन्नाथ और उनके भाई-बहन की वापसी की 'बहुड़ा यात्रा' की तैयारियों के तहत किया जा रहा है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) ने कहा कि बहुड़ा यात्रा से पहले मंदिर के शुद्धीकरण और अन्य अनुष्ठानों को संपन्न कराने के लिए प्रवेश बंद करना जरूरी है। एसजेटीए ने एक बयान में कहा, इस अवधि के दौरान मंदिर परिसर के अंदर प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वे अनुष्ठानों के सुचारू संचालन के लिए मंदिर प्रशासन का सहयोग करें। मंदिर प्रशासन ने अनुष्ठानों के आयोजन में सहयोग और समन्वय के लिए सेवायतों का आभार भी व्यक्त किया।

यह श्रद्धालुओं के लिए 'अदपा मंडप' में देवी-देवताओं के दर्शन का आखिरी दिन था, जहां रथ यात्रा के बाद से भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रह विराजमान हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गईं, क्योंकि यह दिन संध्या दर्शन' के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसे भगवान जगन्नाथ और उनके भाई-बहन की वापसी यात्रा शुरू होने से पहले उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का अंतिम अवसर माना जाता है।

मंदिर के अधिकारी ने कहा, संध्या दर्शन रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक है, क्योंकि गुंडिचा मंदिर से 2.6 किलोमीटर दूर स्थित जगन्नाथ मंदिर में वापसी से पहले श्रद्धालु देवी-देवताओं का अंतिम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बहुड़ा यात्रा के दौरान शुक्रवार को देवी-देवताओं को उनके-अपने रथों पर वापस जगन्नाथ मंदिर ले जाया जाएगा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आने की संभावना को देखते हुए पुलिस, नागरिक प्रशासन और मंदिर प्राधिकारियों ने सुरक्षा तथा भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए हैं। इस बीच, तीनों रथों का 'दखिन मोड़' (दक्षिण दिशा की ओर मोड़ने की प्रक्रिया) बुधवार को पूरा हो गया, जिससे उन्हें वापसी यात्रा के लिए तैयार कर दिया। एडीजीपी सौमेंद्र प्रियदर्शी ने कहा कि बहुड़ा यात्रा के लिए सभी इंतजाम रथ यात्रा के दौरान किए गए प्रबंधों के समान हैं। उत्सव को सुचारू तरीके से संपन्न कराने के लिए विशेष रूप से भीड़ नियंत्रण दल तैनात किए गए हैं।

अभिनेत्री का यौन उत्पीड़न मामला

उच्च न्यायालय ने दो दोषियों की सजा पर रोक लगाने से मना किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोच्चि/भाषा। केरल उच्च न्यायालय ने 2017 में एक अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न के मामले में दो दोषियों की सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया है। अदालत ने अपराध की गंभीरता और उसे अंजाम देने के तरीके को देखते हुए यह राहत देने से मना किया। न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी और न्यायमूर्ति के. वी. जयकुमार की पीठ ने राहत देने से मना करते हुए जनहित के व्यापक पहलुओं, अपराध के सामाजिक प्रभाव और आपराधिक न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को बनाए रखने की ''आवश्यकता'' को ध्यान में रखा।

यह आदेश मामले के आरोपी संख्या पांच सलीम एच. और आरोपी संख्या छह प्रदीप की ओर से दायर अलग-अलग याचिकाओं को खारिज करते हुए पारित किया गया। अदालत ने कहा कि फैसले और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि छह आरोपियों के बीच कथित साजिश साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं और उन्होंने अपनी योजना को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया। पीठ ने कहा, ''प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं (सलीम और प्रदीप) ने अपराध को अंजाम देने में सहायता की और उसे बढ़ावा दिया तथा उनकी मंशा भी अन्य सभी साजिशकर्ताओं के जैसी थी।'' दोनों आरोपियों ने दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ दायर अपनी अपीलों के लंबित रहने तक 20 वर्ष के कारावास की सजा पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि दोनों आरोपी सत्र अदालत के फैसले में कोई ऐसी स्पष्ट कानूनी त्रुटि, प्रत्यक्ष अवैधता या गंभीर खामी नहीं दिखा सके हैं, जिसके आधार पर उनकी सजा पर रोक लगाई जा सके।

अदालत ने कहा, ''इस अंतरिम चरण में हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि सत्र न्यायाधीश के निष्कर्ष इतने अविवेकपूर्ण या त्रुटिपूर्ण हैं कि सजा के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का औचित्य बनता हो।'' उच्च न्यायालय ने इससे पहले नौ जुलाई को भी इस मामले के मुख्य आरोपी सुनील एन. एस. उर्फ पल्सर सुनी की सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया था। सत्र अदालत ने पिछले वर्ष 12 दिसंबर को सुनील, सलीम और प्रदीप सहित छह लोगों को सामूहिक दुष्कर्म के अपराध में 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं, अभिनेता दिलीप और तीन अन्य आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया गया था। यह मामला 17 फरवरी, 2017 को त्रिशूर से कोच्चि जा रही एक अभिनेत्री के अपहरण और चलती कार में उसके यौन उत्पीड़न से जुड़ा है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई 30 तक के लिए स्थगित की

कोलकाता/भाषा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विभिन्न थानों में दर्ज आठ मामलों में दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण देने की तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई 30 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। अदालत ने बनर्जी के वकील को मामले में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का जिक्र उदाहरण के तौर पर नहीं करने को कहा।

न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने मामले की सुनवाई 30 जुलाई तक के लिए स्थगित करते हुए बनर्जी के वकील से कहा कि यदि इस बीच आठ प्राथमिकियों के संबंध में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, तो इसकी जानकारी अदालत को दी जाए। बनर्जी के वकील ने दलील दी कि जब शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, तब उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ दर्ज 17 प्राथमिकियों में उन्हें संरक्षण दिया था। वकील के अनुसार, अदालत ने यह भी कहा था कि भविष्य में उनके खिलाफ अदालत की अनुमति के बिना नई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती। तृणमूल कांग्रेस सांसद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यदि शुभेंदु अधिकारी को यह राहत मिल सकती है, तो बनर्जी को भी मिलनी चाहिए।

हनीमून हत्याकांड

सोनम की जमानत रद्द होने पर राजा के परिजन बोले, 'न्याय की नई उम्मीद जगी'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

इंदौर/भाषा। मेघालय में वर्ष 2025 में हनीमून के दौरान इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी और उनकी विधवा सोनम रघुवंशी की जमानत बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के फैसले का राजा के परिजनों ने स्वागत किया। उनका कहना है कि शीर्ष अदालत के इस आदेश से उनके मन में न्याय मिलने की नई उम्मीद जगी है। उच्चतम न्यायालय ने मेघालय सरकार की याचिका स्वीकार करते हुए सोनम की जमानत रद्द कर दी और उसे तीन सप्ताह के भीतर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

राजा के पिता अशोक रघुवंशी शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद भावुक हो गए। उन्होंने रुंधे गले से 'पीटीआई-भाषा' से कहा,लंबे समय बाद हमें आज थोड़ी खुशी मिली है। उन्होंने कहा, राजा की मौत को एक साल से ज्यादा वक्त हो गया है। मैं आज भी अपने बेटे की तस्वीर देखकर रोता हूं। सोनम को फांसी की सजा होनी चाहिए। रघुवंशी ने कहा कि केवल माता-पिता जानते हैं कि संतान को बड़ा करने में कितनी मेहनत और समय लगता है। उन्होंने कहा,उच्चतम न्यायालय के ताजा आदेश से हमारे मन में नई उम्मीद जगी है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। रघुवंशी ने यह भी कहा कि राजा की हत्या के बाद से सोनम के परिवार ने उनके परिवार से कोई संपर्क नहीं किया है और न ही उनका परिवार अब उनसे कोई बातचीत करना चाहता है।

राजा की मां उमा रघुवंशी ने कहा,मैं उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करना चाहती हूं। मुझे आज अंतर्मन से बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सोनम जैसी महिला को जेल के बाहर होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि सोनम के जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद उनके परिवार को अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता थी। उमा ने कहा, मेरे बेकसूर बेटे को बेरहमी से जान से मार दिया गया था। मुझे भरोसा है कि एक मां की आस नहीं टूटेगी और सोनम को अदालत से कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।

अधिकारियों के मुताबिक, अपने पति राजा की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में सोनम को नौ जून 2025 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया था। वह जमानत पर रिहा होने से पहले शिलांग के जिला कारागार में 10 महीने से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रही थी। राजा और सोनम पिछले वर्ष हनीमून के दौरान मेघालय में लापता हो गए थे। बाद में ईस्ट खासी हिल्स जिले के सोहरा (चेरापूंजी) क्षेत्र में एक झरने के पास गहरी खाई से राजा का शव बरामद हुआ था। मेघालय पुलिस का आरोप है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाह और भाड़े के तीन हत्यारों के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची और इसे अंजाम दिलवाया ताकि उसे रास्ते से हटाया जा सके।

त्रिशूर में संपत्ति विवाद को लेकर बेटे ने बुजुर्ग पिता की पीट-पीटकर हत्या की

त्रिशूर/भाषा। केरल मे त्रिशूर के मडावक्करा में संपत्ति विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने अपने 89 वर्षीय पिता की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान कृष्णन के रूप में हुई है। वह 21 जुलाई को सुबह करीब 10 बजे अपने घर में मृत पाए गए थे। पुलिस ने मामले में कृष्णन के बेटे राधाकृष्णन को गिरफ्तार कर लिया है। वह अपने पिता के घर के पास ही एक अन्य मकान में रहता था।

पुदुक्काड पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम के दौरान पता चला कि कृष्णन की मौत सिर पर किसी कठोर वस्तु से चोट लगने के कारण हुई थी। जांचकर्ताओं को बाद में पता चला कि कृष्णन के घर के निकास द्वारों में से एक खुला हुआ था, जिससे संकेत मिला कि घटना से पहले कोई व्यक्ति घर में आया था। पुलिस के अनुसार, रिश्तेदारों के बयानों से पता चला है कि परिवार के बीच संपत्ति को लेकर विवाद था और कृष्णन ने इस मामले को लेकर अदालत का भी रुख किया था, जिसके बाद अदालत ने राधाकृष्णन को अपने पिता (कृष्णन) के भरण-पोषण का निर्देश दिया था। पुलिस ने बताया कि 20 जुलाई की रात राधाकृष्णन अपने पिता के घर गया था, जहां दोनों के बीच बहस हुई। इस दौरान गुस्से में आकर उसने अपने पिता पर कथित तौर पर हथौड़े से वार कर दिया और फिर उन्हें बेहोश समझकर वह वहां से चला गया। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए बुधवार को राधाकृष्णन और उसके बेटे को हिरासत में लिया था। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के बाद राधाकृष्णन की गिरफ्तारी आधिकारिक रूप से दर्ज की गई।

सिक्किम हादसा

मेरा भाई मोटरसाइकिल खरीदने के बाद शादी करना चाहता था : बबलू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

रांची/भाषा। सिक्किम के नामची ज़िले में निर्माणाधीन एक सुरंग में काम करने वाले मजदूर भोजनावकाश की तैयारी कर रहे थे। 19 साल के बबलू साहू ने पहले अपने बड़े भाई कृष्ण और दूसरों को खाने के पैकेट दिए और उसके बाद बाहर निकल गया। कुछ ही पल बाद, एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ बदल गया। बबलू ने सिक्किम से 'पीटीआई-भाषा' से कहा, मैंने अपने भाई से खाना खा लेने के लिए कहा और बाहर आ गया। अचानक, मुझे धमाके की आवाज सुनाई दी।

जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, ''तो पाया कि सुरंग ध्वस्त हो चुकी थी।'' सोमवार को समरडुंग में राष्ट्रीय जलविद्युत निगम के 'तीस्ता स्टेज सिक्स हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट' में एक निर्माणाधीन सुरंग धंस गई। अधिकारियों के मुताबिक, माना जा रहा है कि यह धमाका मीथेन गैस की वजह से हुआ था। इस घटना में करीब 25 मजदूर सुरंग के अंदर फंस गए थे जिनमें से 22 की मौत हो गई है, जबकि तीन अब भी फंसे हैं।

झारखंड के खूंटी जिले के डाहू गांव का कृष्ण (20) भी उन लोगों में शामिल था जिनके शव तलाश एवं बचाव अभियान के दौरान मलबे से निकाले गए। कृष्ण वेल्डिंग का काम करता था। वह युवा श्रमिक अपने बूढ़े माता-पिता और छोटे भाई की मदद के लिए पिछले कुछ साल से झारखंड के बाहर काम कर रहा था। बबलू ने कहा, मेरे भाई ने हमारे परिवार के लिए एक घर बनवाया था। इस बार उन्होंने कहा था कि वह इस नौकरी से कमाए पैसों से मोटरसाइकिल खरीदेगा। उसके बाद, वो शादी करने वाला था। कृष्ण जून में कुछ समय के लिए घर आया था और दो जुलाई को सिक्किम वापस जाते समय अपने छोटे भाई बबलू को भी साथ ले गया। बबलू मजदूरों के शिविर में भोजनालय में काम करता था और निर्माण स्थल पर मजदूरों को खाना पहुंचाता था। बबलू ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद कृष्ण के शव को झारखंड वापस लाने का इंतजाम किया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि झारखंड के खूंटी, हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूम जिलों के चार लोग इस परियोजना पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तीन लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति अब भी लापता है। बुधवार को हजारीबाग जिले के बरही प्रखंड के तालिया बस्ती के 'एक्सकेवेटर' संचालक जागेश्वर ठाकुर (46) का शव भी बरामद किया गया।

तमिलनाडु सरकार ने द्रमुक की नाश्ता योजना का नाम बदल 'पेरुंथलैवर कामराजर नाश्ता योजना' किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने पूर्ववर्ती द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सरकार की 'मुख्यमंत्री नाश्ता योजना' का नाम बदलकर दिवंगत कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के. कामराज के सम्मान में 'पेरुंथलैवर कामराजर नाश्ता योजना' कर दिया है। राज्य के शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाने वाले नेता के रूप में याद किए जाने वाले कामराज ने गरीबी से निपटने और विद्यालयों में बच्चों का पंजीकरण बढ़ाने के उद्देश्य से 1956 में स्कूली बच्चों के लिए 'मध्याह्न भोजन योजना' की शुरुआत की थी। बाद में, पूर्व मुख्यमंत्री एम. जी. रामचंद्रन ने 1982 में इस योजना का नाम बदलकर पुराची थलाइवर एमजीआर पोषण आहार कार्यक्रम कर दिया था।

इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एम. करुणानिधि और जे. जयललिता ने इस योजना के पोषण संबंधी पहलुओं में और सुधार किए। इसके बाद, एम. के. स्टालिन के नेतृत्व वाली तत्कालीन द्रमुक सरकार ने 2022 में कामराज की जयंती के अवसर पर 15 जुलाई को कक्षा एक से पांच तक के छात्रों के लिए

अपनी प्रमुख 'मुख्यमंत्री नाश्ता योजना' शुरू की थी। स्कूली बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए पहल करने वाले कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री को सम्मान देने और उनके योगदान को फिर से रेखांकित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार ने 15 जुलाई को एक आदेश जारी किया। इसके तहत योजना का नाम बदलकर 'पेरुंथलैवर कामराजर नाश्ता योजना' कर दिया गया है।

इसके साथ ही सरकार ने इस कार्यक्रम का विस्तार करते हुए राज्य भर के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा छह से आठ तक के छात्रों को भी इसके दायरे में शामिल करने की घोषणा की है। इस विस्तार के तहत माध्यमिक विद्यालयों के करीब 15.14 लाख छात्र लाभान्वित होंगे, जिससे राज्य में योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 35 लाख हो जाएगी। द्रमुक के वरिष्ठ नेता दुरईमुरुगन ने सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि यह योजना मूल रूप से किसी विशेष नेता के नाम पर नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री की एक सामान्य पहल के रूप में शुरू की गई थी। दुरईमुरुगन ने कहा, कामराज के नाम पर इसका नाम रखने में कुछ भी गलत नहीं है। इस योजना का संबंध विजय या किसी अन्य मुख्यमंत्री से नहीं है। लेकिन मौजूदा सरकार का पहले से चल रही योजनाओं के नाम बदलना इस बात का संकेत है कि वह नई और अभिनव परियोजनाएं शुरू करने में असमर्थ हैं।

तमिलनाडु सरकार ने 8,193 मंदिरों के लिए गैर-वंशानुगत ट्रस्टियों के आवेदन मांगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) विभाग के अधीन संचालित 8,193 मंदिरों में गैर-वंशानुगत ट्रस्टियों की नियुक्ति के लिए राज्यभर के पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। एचआर एंड सीई विभाग द्वारा जारी घोषणा के अनुसार, यह कदम उन मंदिरों के प्रशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जहां वंशानुगत ट्रस्टी नहीं हैं। इन नियुक्तियों को तमिलनाडु हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम की धारा 49(1) के तहत किया जाएगा, जो विभाग द्वारा प्रबंधित मंदिरों के लिए ट्रस्टियों के बोर्ड के गठन का अधिकार सरकार को प्रदान करती है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मंदिरों की सूची, पात्रता संबंधी शर्तें, आवेदन प्रक्रिया और निर्धारित आवेदन प्रारूप सहित विस्तृत अधिसूचनाएं एचआर एंड सीई विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी हैं।

विभाग ने इच्छुक और पात्र व्यक्तियों से आवेदन करने से पहले सभी दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की अपील की है। आवेदक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं या वेबसाइट से निर्धारित आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित जिले में एचआर एंड सीई विभाग के सहायक आयुक्त के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा किया जा सकता है या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जा सकता है। विभाग ने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त को शाम 5:45 बजे निर्धारित की है।

अधिकारियों ने आवेदकों को सलाह दी है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न हों और अंतिम तिथि से पहले संबंधित कार्यालय तक पहुंच जाएं, ताकि आवेदन निरस्त होने से बचा जा सके। यह नवीनतम अधिसूचना राज्य सरकार की उस व्यापक पहल का हिस्सा है, जिसके तहत एचआर एंड सीई विभाग के अधीन आने वाले मंदिरों में गैर-वंशानुगत ट्रस्टियों के पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जा रहा है।

विभाग ने बताया कि पहले चरण में 1,012 मंदिरों के लिए गैर-वंशानुगत ट्रस्टियों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचनाएं पहले ही जारी की जा चुकी हैं। इसके अलावा, नियुक्ति प्रक्रिया को सुगम बनाने और पात्र उम्मीदवारों के चयन की निगरानी के लिए 14 जिलों में जिला स्तरीय समितियों का गठन भी किया जा चुका है। इन समितियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे आवेदनों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि नियुक्तियां एचआर एंड सीई अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप की जाएं। अधिकारियों के अनुसार, चरणबद्ध नियुक्ति प्रक्रिया का उद्देश्य मंदिरों के प्रशासन में सुधार, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और एचआर एंड सीई विभाग के अधीन कार्यरत धार्मिक संस्थानों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है। पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद इससे तमिलनाडु के हजारों मंदिरों को प्रशासनिक सहयोग मिलने की उम्मीद है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ट्रस्टियों की नियुक्ति से संबंधित सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का राज्यभर में समान रूप से पालन किया जाए।

नीट पूरी तरह विफल हो चुका है, इसे खत्म करने का समय आ गया : एमके स्टालिन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और द्रमुक (डीएमके) अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को लेकर केंद्र सरकार पर हमला तेज करते हुए कहा कि यह परीक्षा अपने घोषित उद्देश्यों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से नीट को समाप्त करने की मांग दोहराई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए स्टालिन ने कहा कि जिस उद्देश्य से नीट लागू की गई थी, वह किसी भी मोर्चे पर सफल नहीं हुई। उनके मुताबिक, इससे न तो छात्रों का शैक्षणिक दबाव कम हुआ, न शिक्षा के व्यावसायीकरण पर रोक लगी और न ही शिक्षा की गुणवत्ता में कोई सुधार आया। उन्होंने कहा कि नीट ने पढ़ाई का केंद्र स्कूलों से हटाकर निजी कोचिंग संस्थानों की ओर कर दिया है, जिससे मेडिकल प्रवेश की तैयारी कर रहे छात्रों और उनके परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक और मानसिक बोझ बढ़ा है।

स्टालिन ने कहा कि नीट की समस्याएं केवल प्रक्रिया से जुड़ी नहीं हैं, बल्कि इसकी पूरी व्यवस्था में ही खामियां हैं। उन्होंने कहा कि हाल के घटनाक्रमों ने तमिलनाडु द्वारा वर्षों से उठाई जा रही चिंताओं को सही साबित किया है। उन्होंने कहा, छात्रों का जारी विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के लिए चेतावनी है। अब समय आ गया है कि केंद्र राज्यों पर भरोसा करे और नीट को समाप्त करे।

स्टालिन की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब उन्होंने एक दिन पहले नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया था। छात्र परीक्षा में कथित अनियमितताओं के बाद सुधार और नीट को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का समर्थन करते हुए स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु ने शुरुआत से ही चेतावनी दी थी कि नीट बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और मेडिकल शिक्षा में असमान अवसरों को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि डीएमके ने शुरू से ही नीट का विरोध किया है, क्योंकि यह सामाजिक न्याय की अवधारणा को कमजोर करता है और ग्रामीण क्षेत्रों, सरकारी स्कूलों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के साथ अन्याय करता है।

स्टालिन ने कहा कि देशभर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों का मुख्य उद्देश्य केवल परीक्षा प्रक्रिया में सुधार नहीं, बल्कि नीट को पूरी तरह समाप्त करना होना चाहिए। उनका कहना था कि केवल प्रक्रियागत बदलावों से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया में निष्पक्षता, पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए नीट को समाप्त करना ही स्थायी समाधान है।

तमिलनाडु के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराते हुए स्टालिन ने कहा कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाने वाला राज्य आज भी नीट को पूरी तरह खत्म करने की मांग पर कायम है। उन्होंने केंद्र सरकार से देशभर के छात्रों की बढ़ती चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए मेडिकल प्रवेश के लिए अधिक न्यायसंगत और समान अवसर सुनिश्चित करने वाली नई व्यवस्था लागू करने की अपील की।

पूछताछ के लिए हिरासत में लिये गए युवक की मौत, परिजनों ने यातना का आरोप लगाया

तूतीकोरिन/भाषा। पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिये गए तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टास्मैक) के एक बिक्री केंद्र में कार्यरत 26-वर्षीय सेल्समैन की बृहस्पतिवार सुबह मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने हिरासत में यातना दिए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अमुथा नगर निवासी एन. अरुणाचलम को शराब की कथित अवैध बिक्री के मामले में पूछताछ के लिए तूतीकोरिन दक्षिण पुलिस ने 17 जुलाई को हिरासत में लिया था। अधिकारी ने बताया कि अरुणाचलम को 18 जुलाई को तूतीकोरिन सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के पांच दिन बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि उसके कब्जे से शराब की 120 बोतलें बरामद कर जब्त की गईं।

अरुणाचलम के परिजनों का दावा है कि हिरासत के दौरान थाने में पुलिस ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसके शरीर पर गंभीर चोटें आईं। परिजनों ने दावा किया कि अस्पताल में मौत से पहले अरुणाचलम ने कहा था कि तीन-चार पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसे चोटें आईं। इसके बाद परिजनों ने उसका शव लेने से इनकार करते हुए अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने अरुणाचलम की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अरुणाचलम की मां परमेश्वरी ने संवाददाताओं से कहा कि पुलिस की पिटाई के कारण उनके बेटे के सिर और पैरों में गंभीर चोटें आई थीं। उन्होंने कहा, मेरे बेटे पर हमला करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और हमें न्याय दिलाने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

कावेरी अस्पताल द्वारा एकीकृत रोबोटिक सर्जरी कार्यक्रम की शुरुआत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। स्थानीय कावेरी अस्पताल द्वारा 'कावेरी 3एक्सचेन्नई' नामक एक एकीकृत रोबोटिक सर्जरी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है जो उन्नत रोबोटिक तकनीक, व्यापक सर्जिकल विशेषज्ञता और उच्च कुशल बहु-विषयक टीम के साथ अस्पतालों में सेवाएं देने के लिए तैयार की गई है।

यह रोबोटिक कार्यक्रम विश्व की सबसे उन्नत तकनीकों में से एक, चौथी पीढ़ी के दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम पर आधारित है। यह कार्यक्रम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजी और नेफ्रोलॉजी सहित कई विषयों को कवर करेगा। इस अवसर पर बोलते हुए, कावेरी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के सह-संस्थापक और कार्यकारी निदेशक डॉ. अरविंदन सेल्वराज ने कहा, 'कावेरी 3एक्स चेन्नई' के साथ, हम एक एकीकृत रोबोटिक सर्जरी इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं जो हमारे चेन्नई के अस्पतालों में उन्नत प्रौद्योगिकी, बहु-विषयक विशेषज्ञता और देखभाल के एकसमान मानकों को एक साथ लाता है।

अब मरीज अपने घर के पास ही कई विशिष्टताओं में व्यापक रोबोटिक देखभाल प्राप्त कर गुणवत्ता और निरंतरता का लाभ उठा सकते हैं।

नीट पेपर लीक रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी दी जाए : कार्ति चिदंबरम

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/चेन्नई। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रश्नपत्र लीक मामलों में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करने संबंधी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया और कहा कि सिर्फ ऐलान करने से व्यवस्था की मूल समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को प्रश्नपत्र लीक होने के कारण पता लगाकर सुधार के लिए कदम उठाने चाहिए और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

कार्ति ने पीटीआई वीडियो से कहा, सिर्फ त्वरित अदालतों की घोषणा कर देने से व्यवस्था की मूल समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसके पीछे कुछ खास कारण हैं, जिनकी वजह से पेपर लीक की घटनाएं बार-बार हो रही हैं। कोचिंग सेंटरों से जुड़े व्यावसायिक हित भी इसका एक कारण हैं। उनके लिए बेहतर और बढ़ा-चढ़ाकर नतीजे

दिखाने का दबाव होता है। इसलिए वे पेपर लीक को बढ़ावा देने और करवाने जैसी हर तरह की गलत गतिविधियों में शामिल होने को तैयार रहते हैं। इससे पहले मोदी ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक संदेश में कहा कि सरकार ने प्रश्नपत्र लीक मामलों में शामिल लोगों को जल्द और सख्त सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा, हमारे युवाओं का कल्याण और उनका भविष्य सबसे महत्वपूर्ण है। यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जो लोग हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

नीट मुद्दे, छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कमल हासन ने केंद्र की आलोचना की

चेन्नई। मक्कल निधि मय्यम (एमएनएम) के संस्थापक एवं मशहूर अभिनेता कमल हासन ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) मुद्दे और छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर भाजपा-नीत केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। हासन ने कहा कि ''देश नाकाम हो गया है'', क्योंकि जब बच्चे सवाल पूछते हैं, तो उन्हें जवाब के बजाय ''बैरिकेड और लाठियां'' मिलती हैं। चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए होने वाली परीक्षा का सीधे तौर पर नाम लिए बिना एमएनएम के नेता एवं राज्यसभा सदस्य ने आरोप लगाया कि यह एक खराब प्रणाली है, जहां ''जिज्ञासा की जगह बेचैनी'' और मेधा की जगह ''अपराध'' ले लेते हैं। सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में हासन ने कहा, ''जब एक बच्चा रोया था, तभी हमें उसकी बात सुननी चाहिए थी। इसके बजाय, हमने तब तक इंतज़ार किया जब तक कि हमारे बहुत सारे बच्चों की मौत नहीं हो गई। ऐसा तंत्र, जिसमें सीखने की जगह कोचिंग, जिज्ञासा की जगह बेचैनी और मेधा की जगह अपराध ले लेते हैं, वह खराब है।'' उन्होंने कहा, ''देश तब नाकाम हो जाता है जब बच्चों को जवाब के बजाय बैरिकेड्स और लाठियां मिलती हैं।''

उत्तर पश्चिम रेलवे

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

मंडल रेल प्रबंधक इंजीनियरिंग, उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिये एवम उनकी ओर से ई-निविदा के माध्यम से प्रचलित नियमो के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्रों में निविदा निम्न कार्यों के लिए क्रमानुसार आमंत्रित की जाती है- **ई-निविदा सूचना सं. 2026-27:** 95 of 2026-27, **कार्य का नाम व स्थान:** Supplying 65 mm guage hard stone machine crushed railway track ballast in stacks and loading in to railway ballast hoppers at Govindi Marwar ballast depot under ADEN/Degana of Jodhpur Division., **अनुमानित लागत रुपये:** 147459000.00, **बयाने की राशि रुपये:** 2949200.00, **ई-निविदा सूचना सं. 2026-27:** 114 of 2026-27, **कार्य का नाम व स्थान:** Platform shelter along with CC Benches at various station in the Jurisdiction of DEN/East in connection with Conversion of Bus Type PF Shelter, **अनुमानित लागत रुपये:** 23081228.03, **बयाने की राशि रुपये:** 461600.00, **ई-निविदा सूचना सं. 2026-27:** 115 of 2026-27, **कार्य का नाम व स्थान:** Provision of new station building with booking office, waiting hall, 2no. waiting room & Retiring room at Makrana station and booking office, waiting hall, waiting room at Nawa City station, **अनुमानित लागत रुपये:** 21519493.28, **बयाने की राशि रुपये:** 430400.00, निविदा सूचना सं. 95 of 2026-27, 114 of 2026-27 & 115 of 2026-27 निविदा प्रस्तुत करने की तिथि 10.08.2026, 17.08.2026 & 13.08.2026 को 15.00 बजे तक) वेबसाइट का विवरण जहाँ पर ई-निविदा देखी व भरी जा सकती है - www.ireps.gov.in

1057-PS/26

हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

अशोक लेलैंड ने पुरानी वाणिज्यिक गाड़ियों के कारोबार के लिए श्रीराम ऑटोमॉल से साझेदारी की

चेन्नई/नई दिल्ली/भाषा। हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड ने पुरानी वाणिज्यिक गाड़ियों की खरीद-बिक्री के लिए श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड के साथ बृहस्पतिवार को साझेदारी की घोषणा की। अशोक लेलैंड ने बयान में कहा कि इस साझेदारी के तहत दोनों कंपनियां प्रमाणित पुरानी वाणिज्यिक गाड़ियों के लिए एक मजबूत और पारदर्शी परिवेश विकसित करेंगी। कंपनी ने कहा कि इससे देशभर के ग्राहकों को अधिक भरोसे और सुविधा के साथ विश्वसनीय तथा गुणवत्ता-सुनिश्चित परिवहन समाधान उपलब्ध होंगे।

अशोक लेलैंड के हल्के वाणिज्यिक वाहन (एलसीवी) कारोबार के प्रमुख विप्लव शाह ने कहा, ''वाणिज्यिक वाहन उद्योग में अशोक लेलैंड की विशेषज्ञता और पुरानी गाड़ियों के क्षेत्र में श्रीराम ऑटोमॉल के मजबूत नेटवर्क एवं ग्राहक आधार को एक साथ लाकर हमारा लक्ष्य ग्राहकों के लिए अधिक मूल्य सृजित करना और उन्हें निर्बाध स्वामित्व अनुभव प्रदान करना है।'' श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड के निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) समीर मल्होत्रा ने कहा, ''हमारा उद्देश्य ग्राहकों को एक पारदर्शी, दक्ष और भरोसेमंद मंच उपलब्ध कराना है जिससे देशभर में पुरानी वाणिज्यिक गाड़ियों की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया सरल हो सके और उन्हें बेहतर मूल्य मिल सके।''

'जन नेता' अब जनता की हो चुकी है : निर्माता वेंकट नारायण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जन नेता' के देशभर के सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने के बाद इसके निर्माता वेंकट के. नारायण ने बृहस्पतिवार को खुशी जताते हुए कहा कि यह फिल्म अब जनता की हो चुकी है। क्रोमपेट के वेत्री सिनेमाघर में फिल्म का पहला शो देखने पहुंचे नारायण ने कहा कि इसे देशभर में रिकॉर्ड संख्या में पर्दों पर प्रदर्शित किया गया है और निर्माता समूह को दर्शकों से भरपूर प्यार व समर्थन की उम्मीद है। अदालती और तकनीकी बाधाओं को पार कर फिल्म के प्रदर्शन पर राहत और खुशी जताते हुए निर्माता ने दर्शकों की प्रतिक्रिया को अद्भुत और बेहद भावुक करने

वाला बताया। पीटीआई-भाषा' से बातचीत में नारायण ने कहा, यह हमारे लिए एक भावुक क्षण है क्योंकि फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हमने काफी कठिनाइयों का सामना किया है। अब जो बीत गया सो बीत गया, हमारा पूरा ध्यान दर्शकों को सिनेमाघरों में बेहतरीन अनुभव देने पर है।

निर्माता ने बताया कि कानूनी और अन्य अड़चनों के दौरान विजय पूरी मजबूती से टीम के साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा कि फिल्म की यह भव्य शुरुआत विजय की लोकप्रियता और उनके विशाल जनाधार को दर्शाती है।

विजय के राजनीति में सक्रिय होने के बाद बड़े पर्दे पर उनकी कमी महसूस होने के सवाल पर नारायण ने कहा कि प्रशंसक और वे खुद उन्हें सिनेमा के जरिए याद करेंगे। मुख्यमंत्री के दोबारा अभिनय क्षेत्र में लौटने की संभावना पर उन्होंने कहा कि यदि अपनी नई जिम्मेदारियों के बीच उन्हें समय मिलता है, तो हर कोई उन्हें फिर से पर्दे पर देखना चाहेगा।

उत्तर पश्चिम रेलवे

खुली ई-निविदा सूचना संख्या: 06 वर्ष 2026-27

निविदा आमंत्रणकर्ता: भारत के राष्ट्रपति की ओर से व उनके लिए उप मुख्य बिजली इंजीनियर, कैरेज कारखाना, उ.प. रेलवे, जोधपुर द्वारा निम्नांकित कार्य के लिए सिर्फ ई-निविदा आमंत्रित की जाती है, **कार्य स्थान सहित कार्य का नाम:** Provision of High capacity IV coupler (500 Amp) & 150 Sq.mm feeder cable for LHB coaches and Power cars (LHB Non AC Coach, LHB AC Coach, LHB AC Double Decker Coach, Power Car, LSLR etc.) at various Division/ Workshop over North Western Railway, **कार्य की अनुमानित लागत:** Rs 1,79,95,628.30, **जमा कराने योग्य धरोहर राशि:** Rs 3,59,900.00 (Only through E-payment), **कार्य पूरा करने की अवधि:** 12 (बारह) माह, **निविदा प्रस्तुत करने व खोलने की तिथि व समय:** इस कार्य के लिए सिर्फ ई-निविदाएं दिनांक 12.08.2026 को 15:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन 15:00 बजे के ठीक बाद खोली जाएगी, **वैबसाइट का विवरण, नोटिस बोर्ड/स्थान जहाँ टेंडर फॉर्म देखा जा सके तथा कार्यालय का पता जहाँ से टेंडर फॉर्म ख़रीदा जा सके:** उक्त एन आई टी व निविदा प्रपत्र को वैबसाईट www.ireps.gov.in पर देखा जा सकता है। नोट: यह एक ई-टेण्डर है। इसलिए इसमें भाग लेने के इच्छुक ठेकेदार ई-टेंडरिंग के द्वारा उल्लिखित वैबसाईट पर ही ई-टेण्डर डालें।

1063-PS/26

हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

उत्तर पश्चिम रेलवे

ई-निविदा सूचना

मंडल रेल प्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर भारत के राष्ट्रपति की ओर से इच्छुक ठेकेदारों से निम्न लिखित कार्य के लिए दिनांक 07.08.2026 को 15.00 बजे तक खुली ई-निविदा आमंत्रित करते है :- **निविदा सख्या:** 106, **कार्य का नाम व स्थान:** सहायक मंडल इंजीनियर / लाईन, बीकानेर के क्षेत्राधिकार में लालगढ़-कोलायत खण्ड पर 60 केजी रेल से 45.877 ट्रेक किमी. टीआरआर (पी) का कार्य करना, **अनुमानित लागत मूल्य:** Rs. 62488594.13, **धरोहर राशि:** Rs. 1249800.00, **निविदा सख्या:** 107, **कार्य का नाम व स्थान:** सहायक मंडल इंजीनियर / लाईन, बीकानेर के क्षेत्राधिकार में सूरतगढ़-लालगढ़ खण्ड पर 60 केजी रेल से 45.657 ट्रेक किमी. टीआरआर (पी) का कार्य करना।, **अनुमानित लागत मूल्य:** Rs. 68815470.93, **धरोहर राशि:** Rs. 1376300.00. **नोट:** अन्य शर्तें रेलवे की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखी जा सकती है।

1060-PS/26

हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

sidbi

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

चेंगलपट्टू जिले में कार्यालय परिसर की आवश्यकता है

सिडबी चेंगलपट्टू जिले में, अधिमानत: महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, मरैमलाई नगर, सिंगपेरूमल कोविल आदि के निकट स्थित भवनों में, एक ही तल (भूतल अथवा प्रथम तल) पर, **1000 वर्ग फीट** (+/- 100 वर्ग फीट) कार्पेट क्षेत्रफल तथा चौपहिया एवं दोपहिया वाहनों की पार्किंग सुविधा सहित कार्यालय परिसर के लिए अवकाश एवं अनुज्ञप्ति (लीव एंड लाइसेंस)/पट्टा (लीज) आधार पर प्रस्ताव आमंत्रित करता है। परिसर तत्काल उपलब्ध होना चाहिए तथा अधिमानत: सुसज्जित होना चाहिए; अथवा बैंक की आवश्यकताओं/विनिर्देशों के अनुसार उसकी साज-सज्जा/पुन: साज-सज्जा का कार्य स्वामी/स्वामियों द्वारा स्वयं के व्यय पर कराया जाएगा। असुसज्जित परिसर पर भी, उसके उपयुक्त पाए जाने पर, विचार किया जाएगा। तकनीकी एवं वित्तीय बोलियों के लिए अपेक्षित प्रारूपों सहित विस्तृत विज्ञापन सिडबी की वेबसाइट **www.sidbi.in** तथा सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट (सीपीपी) पोर्टल **https://eprocure.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा उप महाप्रबंधक का कार्यालय, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल, 756 एल, ओवरसीज़ टावर्स, अन्ना सलाई, चेन्नई-600002, तमिलनाडु, मोबाइल नं. 9810288398, ईमेल आईडी : **sunilkumar@sidbi.in** से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा दस्तावेज़ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन केवल सिडबी की वेबसाइट/सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा। अत: संभावित बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे इन वेबसाइटों को नियमित रूप से देखते रहें। प्रस्ताव जमा कराने की अंतिम तिथि **1 अगस्त, 2026 को 15:00 बजे** तक है।

ह/-
शाखा प्रभारी
सिडबी, चेंगलपट्टू बीओ

दिनांक: 24.07.2026

घर के बाहर शौच को लेकर विवाद में युवक की हत्या, तलवार के वार से गर्दन धड़ से अलग

उदयपुर। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत खटीक मोहल्ले में देर रात घर के बाहर शौच करने की बात को लेकर हुए विवाद में एक युवक की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान देवीलाल उर्फ राजा बाबू खटीक के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, देर रात करीब 10 बजे देवीलाल उर्फ राजा बाबू खटीक और उसके पड़ोसी ओमप्रकाश के बीच घर के पास शौच करने के मुद्दे पर कहासुनी शुरू हुई। विवाद बढ़ते देख देवीलाल के परिजन (उसकी मां और भाई) भी घर से बाहर आ गए और दोनों पक्षों के बीच बीच-बचाव करने लगे। इसी दौरान आरोपी ओमप्रकाश अचानक अपने घर के भीतर गया और तलवार निकाल लाया। उसने देवीलाल की गर्दन पर तलवार से जोरदार वार कर दिया, जिससे देवीलाल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही गोगुंदा थानाधिकारी प्रवीण सिंह राजपुरोहित पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। शव का मोर्चरी में रखवाया जाना: पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर मृतक के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए गोगुंदा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ओमप्रकाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

अजमेर अदालत परिसर को बम से उड़ाने की झूठी धमकी दी, आरोपी गिरफ्तार

जयपुर। पुलिस ने अजमेर जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की झूठी धमकी देकर दहशत फैलाने के आरोप में एक व्यक्ति को गुजरात से गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। इसके अनुसार आरोपी ने फर्जी ई-मेल आईडी के माध्यम से न्यायालय की आधिकारिक ई-मेल पते पर बम धमाके की धमकी देने वाला संदेश भेजा था। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है। अजमेर के जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अगरवाला ने बताया कि इसी महीने 17 जुलाई को जिला एवं सत्र न्यायालय, अजमेर की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर एक धमकी भरा ई-मेल प्राप्त हुआ जिसमें न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके बाद न्यायालय प्रशासन की ओर से इसे बारे में सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(1)(बी) एवं आईटी कानून के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। साइबर प्रकोष्ठ ने फर्जी ई-मेल की तकनीकी जांच, डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण तथा आसूचना संकलन के आधार पर आरोपी की पहचान करते हुए फलदू हार्दिक पुत्र रमेशचंद्र पटेल (40) को गिरफ्तार किया। वह गिर सोमनाथ जिला के प्रभास पाटन का रहने वाला है।

सड़क हादसे में बाइक सवार तीन लोगों की मौत

जयपुर। राजस्थान के करौली जिले में सड़क हादसे में बाइक पर सवार तीन लोग की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी पुलिस के अनुसार यह हादसा कोतवाली थाना क्षेत्र के मैगजीन इलाके में बुधवार शाम को तब हुआ जब एक बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। उसके अनुसार दो युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। मृतकों की पहचान आशीष (16) तथा हर्ष (16) और पवन (21) के रूप में हुई है। तीनों रिश्तें में भाई थे और हादसे के समय बाइक से घर लौट रहे थे। पुलिस के अनुसार बाइक के सामने अचानक कोई मवेशी आने के कारण संभवत: यह हादसा हुआ। ट्रक को जब्त कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

'अंगदान संकल्प अभियान' में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर

जयपुर। अंगदान महाअभियान को मिल रहे जनसमर्थन के चलते राजस्थान 'अंगदान संकल्प अभियान' में देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। इसके अनुसार राज्य में 1.08 लाख से अधिक नागरिकों ने अंगदान का संकल्प लिया है। प्रमुख शासन सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) गायत्री राठौड़ ने बताया कि राज्य में जारी अंगदान जन-जागरूकता अभियान को व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आमजन की बढ़ती भागीदारी के कारण राजस्थान ने अंगदान संकल्प अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।उन्होंने बताया कि 22 जुलाई तक राज्य में 1,08,904 नागरिकों ने अंगदान का संकल्प लिया है। यह अभियान तीन अगस्त तक चलेगा। उनके अनुसार इस अभियान में फिलहाल प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है जबकि दोनों राज्यों के बीच संकल्प लेने वालों की संख्या के लिहाज से महज 8,136 का अंतर रह गया है। राठौड़ ने बताया कि जिला स्तर पर झुंझुनूं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 13619 अंगदान संकल्पों के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद हनुमानगढ़ (12828), चूरू (10780), जयपुर (8152), अजमेर (6722) तथा सीकर (5956) प्रमुख जिलों में शामिल हैं। उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में अंगदान का संकल्प लेने का आह्वान किया है क्योंकि एक व्यक्ति का अंगदान कई गंभीर रोगियों को नया जीवन दे सकता है।

राजस्थान में अनेक जगह भारी बारिश

जयपुर। दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रभाव से राजस्थान के अनेक हिस्सों में जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को भी कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह तक पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी भाग में अधिकांश स्थानों पर मध्यम से भारी और एक-दो स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हुई। इसी तरह, राज्य के पश्चिमी भाग में भी अनेक स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक 17 सेंटीमीटर बारिश जगपुरा (बांसवाड़ा) में हुई। इसके अलावा, भीलवाड़ा के आसींद में 16 सेंटीमीटर, अजमेर के जवाजा में 12 सेंटीमीटर, गंगानगर के सादुलशहर में 11 सेंटीमीटर, प्रतापगढ़ के धरियावद में 10 सेंटीमीटर, हनुमानगढ़ और झालावाड़ के अकलेरा में आठ-आठ सेंटीमीटर तथा डूंगर के निथुआ में छह सेंटीमीटर बारिश हुई। इसी तरह, राजसमंद, बारां, जोधपुर, पाली, बूंदी और सिरोही जिलों में एक से पांच सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र, जयपुर के अनुसार, राज्य के अधिकांश भागों में अगले चार-पांच दिन मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अजमेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर संभागों में 23 से 25 जुलाई के दौरान मध्यम से भारी तथा कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभागों के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

संबल सखियों के माध्यम से साकार होगा विकसित राजस्थान 2047 का संकल्प : शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से तीन माह पहले शुरू किया गया संबल सखी अभियान आज महिला सशक्तीकरण का जनआंदोलन बन चुका है। संबल सखियों द्वारा राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जा रही है।

मुख्यमंत्री बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर संबल सखी यंग प्रोफेशनल्स से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 का संकल्प संबल सखियों के समर्पण से ही साकार होगा। उन्होंने कहा कि सेवा शिविरों, वंदे गंगा अभियान में संबल सखियों ने योजनाओं और सेवाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

मुख्यमंत्री ने संबल सखियों से संवाद करते हुए उनके विचार जाने। संबल सखियों ने कहा कि मुख्यमंत्री की इस पहल पर उन्हें समाज के बीच जाकर सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है। वास्तविक लाभार्थियों को पहुंच रहे लाभ से उनको प्रेरणा मिलती है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उत्थान के लिए मिला यह अवसर उन्हें पूरी निष्ठा और तन्मयता के साथ निभाना चाहिए। साथ ही, योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने और समस्या के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाएं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चार प्रमुख जातियों किसान, मजदूर, महिला और युवा का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो रहा है। राज्य सरकार किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, पर्याप्त सिंचाई जल, और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि उनकी आय और जीवन स्तर में सुधार हो सके। इसी प्रकार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार रोजगार के साथ स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रही है। प्रदेश में अब तक 1 लाख 78 हजार पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं तथा 1 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। निजी क्षेत्र में भी साढ़े चार लाख युवाओं को रोजगार मिला है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने और अगली पीढ़ी के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण को लेकर प्रतिबद्ध हैं। हमारी डबल इंजन सरकार धरातल पर काम कर आमजन के जीवन को सुगम बना रही है। रोडमैप बनाकर पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं, जिसका असर धरातल पर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। मई, जून और जुलाई के जिन महीनों में राज्य पूर्व में अन्य राज्यों से बिजली खरीदता था, वहीं इस बार राजस्थान ने न केवल अपनी जरूरतें पूरी की, बल्कि बिजली उत्पादन में सरप्लस उत्पादन कर अन्य राज्यों को भी बिजली बेचने का ऐतिहासिक कार्य किया है। साथ ही, सड़कों के उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण के महत्वपूर्ण कार्य करवाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने सेवा शिविरों की प्रभावशीलता का उल्लेख करते हुए बताया कि शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से वर्षों पुरानी जटिल समस्याओं का निस्तारण हुआ। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों की अवधि को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है।

सुमेरपुर के राजकीय महाविद्यालय में कैबिनेट मंत्री कुमावत ने किया पौधारोपण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पाली। पाली जिले के सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के तखतगढ़ में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर स्थापित हुआ है। क्षेत्र के नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय भवन में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने शिरकत की। उन्होंने महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रथम वर्ष के नवागंतुक विद्यार्थियों का तिलक लगाकर और मुंह मीठा कराकर आत्मीय स्वागत किया गया।

मंत्री कुमावत ने विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य और सफल शैक्षणिक जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह आधुनिक और नवनिर्मित महाविद्यालय भवन क्षेत्र के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करेगा। यह परिसर विद्यार्थियों की प्रतिभा और क्षमताओं को तराशकर उन्हें नई दिशा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कार्यक्रम के दौरान 'हरियालो राजस्थान-एक पेड़ मां के नाम' के अंतर्गत एक वृहद पौधरोपण कार्यक्रम चलाया गया। कैबिनेट मंत्री, कॉलेज प्रशासन, अतिथियों और छात्र-छात्राओं ने मिलकर महाविद्यालय परिसर में 400 पौधों का रोपण किया। मंत्री ने युवाओं से इन पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया।

प्रदूषणकारी वाहनों, सी एण्ड डी वेस्ट तथा औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए प्रभावी कदम : मुख्य सचिव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए गठित समिति की समीक्षा बैठक गुरुवार को कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई। बैठक में राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब के मुख्य सचिव अपने-अपने राज्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। राजस्थान की ओर से मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राजस्थान सचिवालय स्थित एनआईसी कक्ष से बैठक में भाग लिया। बैठक में केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), नीति आयोग, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

डॉ. सोमनाथन ने राज्यों को वायु प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने तथा सभी संबंधित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क धूल नियंत्रण, पुराने एवं प्रदूषणकारी वाहनों के चरणबद्ध प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (सी एंड डी वेस्ट) के वैज्ञानिक प्रबंधन, निर्माण स्थलों की प्रभावी निगरानी, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, वायु गुणवत्ता की नियमित निगरानी, पराली एवं बायोमास जलाने पर रोक तथा पौधारोपण जैसे उपायों को प्राथमिकता के साथ लागू करने पर जोर दिया। बैठक में राज्यों द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना तथा अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए कैबिनेट सचिव ने विभिन्न उपायों के समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राजस्थान की ओर से राज्य में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार 'परिवर्तन' कार्यक्रम के तहत एनसीआर क्षेत्र में 5,268 पुराने एवं प्रदूषणकारी वाहनों के चरणबद्ध प्रतिस्थापन की दिशा में कार्य कर रही है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का लगातार विस्तार किया जा रहा है, जिससे स्वच्छ एवं टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क धूल नियंत्रण के लिए यांत्रिक सड़क सफाई (मैकेनाइज्ड स्वीपिंग) सहित अन्य प्रभावी उपायों को प्राथमिकता के साथ लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (सी एंड डी वेस्ट) के वैज्ञानिक प्रबंधन, निर्माण स्थलों की प्रभावी निगरानी, वायु गुणवत्ता की नियमित निगरानी, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण तथा पराली एवं बायोमास जलाने की रोकथाम के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में संचालित 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत प्रदेशभर में व्यापक स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) तथा केंद्र सरकार के साथ नियमित समन्वय बनाए रखते हुए निर्धारित कार्ययोजना के अनुरूप आवश्यक कदम उठा रही है। मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।

ये आक्रोश अब थमने वाला नहीं : अशोक गहलोत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई व राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के प्रकरण की आलोचना करते हुए बुधवार को कहा कि इससे देश के लोगों में आक्रोश है।

उन्होंने कहा कि यह आक्रोश अब थमने वाला नहीं है। गहलोत ने आरोप लगाया कि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मनसूबे अच्छे नहीं है।

कांग्रेस नेता ने यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में कहा,राहुल गांधी के साथ जो कल हरकत की है... ये हरकत भी इन (केंद्र में सत्तारूढ़) लोगों को ले डूबेगी। पूरे देश में घर-घर में आक्रोश पैदा हो गया है। क्योंकि लोग (पहले ही) बेरोजगारी व महंगाई जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा,... इस घटना के बाद आम जनता, हर परिवार खुलकर बोलने लगा है कि क्या तमाशा लगा रखा है इन लोगों ने? मैं समझता हूं कि अब ये आक्रोश थमने वाला नहीं है। यह बढ़ेगा क्योंकि जनता समझ चुकी है इनकी हरकतों को व मनसूबों को।

उल्लेखनीय है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आवास के बाहर धरना देने के बाद हिरासत में ले लिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा व उसके नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा,इनके मनसूबे अच्छे नहीं हैं, देश हित में नहीं हैं। ये चाहते हैं देश से लोकतंत्र खत्म हो और पचास साल हम ही राज करें चीन की तरह।

ई-मित्र वॉट्सऐप सेवा का दायरा बढ़ा

जयपुर विद्युत वितरण निगम एवं स्वायत्त शासन विभाग की 21 नई सेवाएं हुईं शामिल

जयपुर। राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को घर बैठे सरल, त्वरित एवं पारदर्शी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ई-मित्र वॉट्सऐप सेवा का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब इस प्लेटफॉर्म पर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) तथा स्वायत्त शासन विभाग की 21 नई सेवाएं भी उपलब्ध करा दी गई हैं। इससे नागरिक बिजली संबंधी सेवाओं के साथ-साथ विभिन्न नगरीय सेवाओं का लाभ भी सीधे अपने मोबाइल पर वॉट्सऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के विशिष्ट सचिव एवं आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 1 जुलाई को आयोजित 'नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस' के दौरान ई-मित्र वॉट्सऐप सेवा का शुभारंभ किया गया था। शुभारंभ के बाद से ही नागरिकों का इस सेवा के प्रति उत्साह लगातार बढ़ रहा है। अब तक 1.40 लाख से अधिक बार नागरिक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त कर चुके हैं, जो इस पहल की बढ़ती लोकप्रियता और उपयोगिता का प्रमाण है।

गुप्ता ने बताया कि सेवा के प्रथम चरण में 51 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई गई थीं। अब नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसमें 21 नई सेवाओं का विस्तार किया गया है, जिससे अधिक से अधिक सरकारी सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो रही हैं। राज्य सरकार द्वारा इस सेवा के लिए वॉट्सऐप नंबर 9461062705 जारी किया गया है।

पशुपालन मंत्री ने शहरी फॉलो-अप शिविर में बांटे पट्टे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के तखतगढ़ नगरपालिका परिसर में एक विशेष दौरे के दौरान विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। मंत्री कुमावत ने स्वायत्त शासन विभाग की ओर से चलाए जा रहे 'शहरी सेवा शिविर अभियान-2026' के अंतर्गत आयोजित फॉलो-अप शिविर का औचक निरीक्षण और विस्तृत अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया और उन्हें मौके पर ही राहत राशि व प्रमाण-पत्र सौंपे। शिविर के दौरान कैबिनेट मंत्री ने आमजन को आर्थिक संबल प्रदान करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के चेक वितरित किए। कुमावत ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत मकान पक्का करने के सपने को साकार करते हुए 11 लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में 50-50 हजार रुपये के चेक सौंपे। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 7 लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में 15-15 हजार रुपये की ऋण सहायता राशि प्रदान की।

शिविर में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल करते हुए वर्षों से लंबित मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। कैबिनेट मंत्री कुमावत ने धारा 69-क के तहत लंबे समय से अपने आशियाने के मालिकाना हक का इंतजार कर रहे 9 लाभार्थियों को आवासीय पट्टे वितरित किए। इसके साथ ही कुमावत ने संपत्ति के हस्तांतरण और राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त करते हुए 7 नागरिकों को नामांतरण (म्यूटेशन) प्रमाण-पत्र सौंपे गए।

प्रधानमंत्री का जवाब नाकाफी है, प्रधान के इस्तीफे तक जंतर-मंतर नहीं छोड़ेंगे : कॉजपा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की अपनी मांग को फिर से दोहराते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि प्रश्नपत्र लीक के मामलों में कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा में जवाबदेही के मुद्दे पर कोई बात नहीं की गई है।

मोदी ने बृहस्पतिवार सुबह 'एक्स' पर एक पोस्ट में प्रश्नपत्र लीक में शामिल लोगों को जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालत बनाने की घोषणा की और कहा, ''हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है।'' मोदी ने पोस्ट में कहा, ''हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।'' राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रश्नपत्र लीक को लेकर युवाओं के लगातार जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि प्रश्नपत्र लीक के मामलों में शामिल लोगों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए सरकार ने त्वरित अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है।

प्रधानमंत्री के 'एक्स' पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कॉजपा के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधान की एक तस्वीर साझा की जिस पर लिखा था, मेरा नाम कुछ नहीं है।'' वहीं, कॉजपा ने पोस्ट किया, ''धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए।'' कॉजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया का स्वागत किया, लेकिन कहा कि यह लगभग डेढ़ महीने के विरोध-प्रदर्शनों के बाद आई और बार-बार प्रश्नपत्र लीक होने के पीछे के मुख्य सवाल का जवाब नहीं दिया। रांका ने कहा, ''पहली बात तो ये है कि अच्छी बात है कि डेढ़ महीने के विरोध-प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री ने आखिरकार इस पर ध्यान दिया है। शायद उनके विदेश दौरे खत्म हो गए हैं और वह भारत लौट आए हैं, जो कि एक अच्छी बात है।''

उन्होंने कहा, ''जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, हम यह जगह नहीं छोड़ेंगे।''

प्रधानमंत्री 'मंगल पर पहुंचने' का श्रेय लेते हैं, अब अपनी कार्रवाइयों की जिम्मेदारी भी लें : प्रियंका

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने बृहस्पतिवार को छात्रों के प्रदर्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वह मंगल ग्रह पर ''पहुंचने'' का श्रेय लेते हैं, इसलिए अब उन्हें अपनी कार्रवाइयों की जिम्मेदारी लेनी होगी। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में प्रियंका ने कहा कि ''प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि उन्हें बच्चों की परवाह है, जबकि कल रात ही उन्होंने उन पर आंसू गैस छुड़वाई और पिटवाया।'' उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, ''क्या आपने कभी हमारे लोकतंत्र के इतिहास में देखा है कि सत्तारूढ़ खेमे के सांसद बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हों। यह कितने सत्रों से चल रहा है और वे संसद सत्र नहीं चला पा रहे हैं। बाहर क्या हो रहा है। वह कमजोर और कायर हैं।'' मध्य दिल्ली के कुछ इलाकों में इंटरनेट बंद होने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर प्रियंका गांधी ने कहा, ''क्या हम लोकतंत्र में रह रहे हैं? जरा सोचिए, बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं...उन्होंने इंटरनेट काट दिया है, वे क्या कर रहे हैं? छात्र आतंकवादी नहीं हैं।

उनके माता-पिता परेशान होंगे, उनके परिवार परेशान होंगे, वे किसी से संपर्क नहीं कर सकते। वे उन पर आंसूगैस छोड़ रहे हैं, उन्हें पीट रहे हैं। यह किस तरह का लोकतंत्र है।'' मीडिया से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि क्या उसने पूछा है कि प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर कैसे पोस्ट कर रहे हैं कि उन्हें बच्चों की परवाह है, जबकि कल रात उन्होंने छात्रों पर आंसूगैस छोड़ी और उन्हें पीटा''।

जंतर मंतर पर जख्मी हुए एसीपी ने कहा, 'मेरे सिर पर पत्थर लगा'

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर कथित पथराव में जख्मी हुए सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) जय प्रकाश ने बृहस्पतिवार को बताया कि धरना स्थल पर बुधवार शाम लगभग 4.30 बजे भीड़ बढ़कर 5,000 से 6,000 लोगों की हो गई थी।

प्रकाश ने बताया, मेरे सिर पर पत्थर लगा था। जब मेरे सहकर्मी मुझे विरोध स्थल से निकालकर आरएमएल अस्पताल ले गए, तब मेरे सिर से खून बह रहा था। मेरे सिर में मामूली फ्रैक्चर है और आगे का इलाज किया जा रहा है। एसीपी उन दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों में शामिल हैं, जो संसद मार्ग के पास बुधवार को प्रदर्शनकारियों द्वारा किए कथित पथराव में घायल हो गए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, संसद मार्ग पर कल हुई हिंसा की घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले में आगे की जांच जारी है। पंजाबी बाग उपमंडल के एसीपी जय प्रकाश ने घटना को याद करते हुए बताया कि उन्हें सुबह सात बजे से जंतर-मंतर के पास तैनात किया गया था।

मुख्यमंत्री की पत्नी की ओर से दर्ज मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा असम पुलिस के सामने पेश हुए

गुवाहाटी/भाषा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा असम पुलिस की अपराध शाखा के सामने पेश हुए। यह मामला मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी की ओर से दर्ज कराया गया था। खेड़ा ने प्रेसवार्ता में आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री शर्मा की पत्नी के पास कई पासपोर्ट और देश के बाहर संपत्ति है। इसके बाद खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। राज्यसभा सदस्य खेड़ा तीसरी बार पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पहुंचे।

अपराधा शाखा थाने के बाहर पत्रकारों से खेड़ा ने कहा, ''जब भी वे मुझे बुलाते हैं, मैं आने की कोशिश करता हूं।'' वह पिछली दो तारीखों पर पेश नहीं हो पाए थे क्योंकि एक बार तबीयत ठीक नहीं थी और दूसरी बार वह राज्यसभा चुनाव की औपचारिकताओं में व्यस्त थे। खेड़ा ने कहा, ''लेकिन जब भी मुझे बुलाया जाता है, मैं यहां आने की पूरी कोशिश करता हूं। मुझसे पहले भी दो बार पूछताछ हो चुकी है और अब मुझे फिर से बुलाया गया है। मैं कानून का पालन करूंगा तथा जांच में पूरा सहयोग करूंगा।'' मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने छह अप्रैल को कांग्रेस के मीडिया व प्रचार विभाग के अध्यक्ष खेड़ा तथा उनके साथ मिलीभगत करने वाले अन्य सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। यह मामला भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था, जिनमें धारा 175 (चुनाव से संबंधित झूठा बयान) और धारा 318 (धोखाधड़ी) शामिल हैं।

मुर्शिदाबाद समपार फाटक दुर्घटना के आरोपी गेटमैन को मौत की सजा मिलनी चाहिए : शुभेंदु अधिकारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बहरामपुर/भाषा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने पुलिस को मुर्शिदाबाद समपार फाटक हादसे की जांच में तेजी लाने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष को गिरफ्तार गेटमैन के लिए मौत की सजा की मांग करनी चाहिए। इस घटना में पांच लोगों की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों के परिवारों से मिलकर उन्हें पांच-पांच लाख रुपये के चेक सौंपने के बाद ये निर्देश दिए।

गोविंदपुर समपार फाटक पर 17 जुलाई को एक ट्रेन ने स्कूल की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे चार विद्यार्थियों समेत पांच लोगों की मौत हो गई।

उन्होंने कहा, ''मैं पुलिस को साफ निर्देश दे रहा हूं कि वे आरोपी गेटमैन के हिरासत में रहते हुए ही अपनी जांच पूरी करें। उन्हें उसकी हिरासत के दौरान ही आरोपपत्र दाखिल करना चाहिए। हिरासत के दौरान मुकदमा चलाया जाना चाहिए, ताकि उसे मौत की सजा मिल सके।'' शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद के पुलिस अधीक्षक (एसपी) और जिलाधिकारी (डीएम) को जांच पर बारीकी से नजर रखने का निर्देश दिया और कहा कि इसके लिए एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने स्थानीय विधायक भरत कुमार झावर से भी कहा कि वह इस मामले पर नजर रखें और उन्हें लगातार अद्यतन जानकारी देते रहें।

मुख्यमंत्री दोपहर के समय हेलिकॉप्टर से बहरामपुर पहुंचे और फिर सड़क मार्ग से गोविंदपुर गए। रास्ते में वह कुछ देर के लिए दुर्घटना स्थल पर रुके और फिर गोविंदपुर गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में पीड़ित परिवारों से मिले। इस मौके पर राज्य के मंत्री गौरीशंकर घोष, डीएम राजर्षि मित्रा, एसपी सचिन मक्कर, बेलडांगा के विधायक झावर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

शाह ने बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली, अंतर-मंत्रालयी दल असम आएगा : मुख्यमंत्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गुवाहाटी/भाषा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। शर्मा ने बताया कि नुकसान का आकलन करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल जल्द ही राज्य का दौरा करेगा। इस वर्ष बाढ़ से अब तक कम से कम 41 लोगों की मौत हो चुकी है और 6.50 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं।

शर्मा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, कुछ देर पहले मुझे गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया। असम में बाढ़ की अप्रत्याशित स्थिति को देखते हुए उन्होंने मुझे बताया कि ''नुकसान का आकलन करने और प्रभावित लोगों की आजीविका के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक केंद्रीय सहायता तय करने में मदद के वास्ते एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल जल्द ही राज्य का दौरा करेगा।''

उन्होंने इस मुश्किल समय में असम के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए शाह का आभार जताया। शर्मा ने बाद में गोलाघाट जिले के कोमरबोंधा में राहत शिविर का निरीक्षण करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा, अमित शाह ने आज मुझे फोन किया और स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों वाली केंद्रीय टीम

आज या कल राज्य का दौरा करेगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि खेत डूब गए हैं, महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट हो गए हैं और पशु बह गए हैं। शर्मा ने कहा, लोग मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं और सरकार उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेगी। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित पूर्वी जिलों का लगातार दूसरे दिन दौरा किया।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक अन्य पोस्ट में कहा, असम में बाढ़ से हुई तबाही का पैमाना अकल्पनीय है। इस आपदा से 25 जिलों के 1,800 से अधिक गांवों में नौ लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अब तक 41 लोगों की जान चली गई हैं और हजारों पशु बह गए हैं। उन्होंने कहा कि ऊपरी इलाकों में बादल फटने की घटनाओं और स्थानीय स्तर पर सामान्य से 436 प्रतिशत अधिक हुई भारी बारिश के कारण उन गांवों में भी बाढ़ आ गई है, जहां हाल के वर्षों में इतनी बड़ी तबाही नहीं देखी गई थी। शर्मा ने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए पूरी सरकार के संयुक्त प्रयास के तहत पूरी ताकत से कदम उठाए जा रहे हैं।

मेट्रो स्टेशनों के बंद रहने के दूसरे दिन भी लोग परेशान, यात्रा का समय और खर्च बढ़ा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली मेट्रो के कुछ स्टेशनों पर मेट्रो सेवाएं बृहस्पतिवार को लगातार दूसरे दिन भी प्रभावित रहीं। सत्रह मेट्रो स्टेशनों के बंद रहने से कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों और अन्य यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उन्हें लंबे वैकल्पिक मार्ग अपनाने पड़े जिससे उनका यात्रा खर्च भी बढ़ गया। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ, जब जंतर-मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के विरोध-प्रदर्शन में लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने सोशल मीडिया मंच एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय

सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं।

बाद में, डीएमआरसी ने झंडेवालान मेट्रो स्टेशन पर भी सेवाएं बंद कर दीं। इन्हीं 17 मेट्रो स्टेशनों पर सेवाएं बुधवार को भी बंद कर दी गई थीं। जोर बाग मेट्रो स्टेशन के बाहर महिपाल ढाका नामक व्यक्ति ने बताया कि वह काम के सिलसिले में रिठाला जा रहे थे, लेकिन स्टेशन बंद मिलने के बाद उन्हें यात्रा के लिए किसी वैकल्पिक साधन की तलाश करनी पड़ी। उन्होंने कहा, ''मुझे काम के लिए रिठाला जाना है, लेकिन अब मुझे किसी दूसरे परिवहन साधन की तलाश करनी पड़ेगी, जिसमें ज्यादा खर्च आएगा।'' उन्होंने कहा, ''बहुत से लोग रोजाना मेट्रो पर निर्भर रहते हैं। हमें देर हो जाती है और फिर अपने कार्यालयों में देरी से आने को लेकर जवाब देना पड़ता है।'' वहीं, एक अन्य यात्री अमित कुमार ने कहा कि बार-बार मेट्रो सेवाएं बंद होने से उनकी दिनचर्या प्रभावित हो गई है और समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए उन्हें डेढ़ घंटे पहले घर से निकलना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा, ''मैं कल भी कार्यालय देर से पहुंचा था। आमतौर पर मैं सुबह आठ बजे घर से निकलता हूं, लेकिन आज समय पर पहुंचने के लिए मुझे सुबह साढ़े छह बजे ही निकलना पड़ा। शाम के समय भी लोग रात के 10 बजे तक घर पहुंच रहे हैं, क्योंकि मेट्रो स्टेशनों के बंद होने, मार्गों में बदलाव और भारी यातायात के कारण उन्हें काफी देरी का सामना करना पड़ रहा है।''

'उम्मीद' पोर्टल पर 7,99,978 वक्फ संपत्तियों को दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हुईः सरकार

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने लोकसभा को बताया कि 17 जुलाई तक कुल 7,99,978 वक्फ संपत्तियों को 'उम्मीद' पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रीजीजू ने बुधवार को एक सवाल के लिखित जवाब में लोकसभा में कहा कि इन वक्फ संपत्तियों में से 6,17,102 संपत्तियों को मान्यता दी गई है, वहीं 91,623 वक्फ संपत्तियां अपलोडिंग के अलग-अलग चरण में लंबित हैं। उन्होंने कहा कि 91,253 वक्फ संपत्तियों को सत्यापन के दौरान खारिज कर दिया गया है। रीजीजू ने कहा कि 17 जुलाई, 2026 तक कुल 7,99,978 वक्फ संपत्तियों को 'उम्मीद' सेंट्रल पोर्टल-2025 पर अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

स्कूटर की बैटरी फटने से तीन भाई घायल हुए

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में बृहस्पतिवार सुबह एक झुग्गी के अंदर चार्ज हो रही इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी में कथित तौर पर विस्फोट होने से तीन भाई झुलस गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, यह घटना सुबह करीब सात बजे उत्तर पश्चिम दिल्ली के एसएस नगर इलाके में हुई। अधिकारियों ने बताया कि जब बैटरी में विस्फोट हुआ और इस कारण आग लगी, उस वक्त 45-वर्षीय विजय झुग्गी में सो रहा था। घटना के समय परिवार के बाकी सदस्य झुग्गी के बाहर थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, आग बुझाने और बचाव की कोशिशों के दौरान विजय और उनके भाई अजय (35) एवं बिरजू (23) झुलस गए। पीड़ितों को पहले दीपचंद बंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें लोक नायक अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर है। हालांकि, विजय और बिरजू ज़्यादा बुरी तरह झुलस गए हैं। पुलिस ने बताया कि विस्फोट की सूचना सुबह अशोक विहार थाने को मिली, जिसके बाद पुलिस की एक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। अपराध टीम ने भी घटनास्थल का मुआयना किया।

प. एशिया संघर्ष : भारतीय विमानन कंपनियों ने पाबंदियों के कारण 20 जुलाई तक 26,000 उड़ानें रद्द कीं

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने बृहस्पतिवार को लोकसभा को बताया कि अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते हवाई क्षेत्र पर लगी पाबंदियों के कारण भारतीय विमानन कंपनियों ने 20 जुलाई तक करीब 26,000 अंतरराष्ट्रीय उड़ान रद्द कर दी हैं और इसके अलावा, विमानों के आवागमन में देरी और उनके रास्ते में परिवर्तन भी हुआ है।

नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि मौजूदा संकट के कारण एयरलाइंस को राजस्व का काफी नुकसान हो रहा है और वे परिचालन जारी रखते हुए इसके असर को कम करने के लिए कदम उठा रही हैं। फरवरी के आखिर में शुरू हुए इस संघर्ष ने विमानन उद्योग पर काफी असर डाला है, जो पश्चिम एशिया में ईंधन की ऊंची कीमतों और हवाई क्षेत्र पर पाबंदियों से जूझ रहा है। मोहोल ने कहा, अमेरिका-ईरान संघर्ष ने हवाई क्षेत्र पर लगी पाबंदियों के कारण अंतरराष्ट्रीय उड़ान परिचालन में काफी रुकावट डाली है, जिससे बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द हुई हैं (20 जुलाई 2026 तक भारतीय विमानन कंपनियों द्वारा 26,000 उड़ानें), साथ ही कई विमानन कंपनियां और हवाई अड्डों पर कई विमानों के मार्ग बदलने पड़े या उनके आवागमन में देरी हुई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले खतरों से निपटने के लिए यात्रियों, चालक दल और विमान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई परामर्श जारी किए हैं।

टीएमसी विधायक मदन मित्रा के बड़े बेटे भर्ती घोटाले की जांच के संबंध में ईडी के समक्ष पेश हुए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा के बड़े बेटे स्वरूप मित्रा, कथित नगरपालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए बृहस्पतिवार को यहां सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दफ्तर में पेश हुए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उनके पेश होने से एक दिन पहले, केंद्रीय एजेंसी ने इसी मामले में उनके छोटे भाई शुभरूप मित्रा से लगभग नौ घंटे तक पूछताछ की थी।

ईडी ने मदन मित्रा की पत्नी अर्चना मित्रा को भी समन भेजा है, जिन्हें शुक्रवार को जांचकर्ताओं के सामने पेश होना है, जबकि राज्य के पूर्व मंत्री को 29 जुलाई को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। स्वरूप मित्रा बृहस्पतिवार सुबह ईडी दफ्तर पहुंचे। सीजीओ कॉम्प्लेक्स में जाने से पहले उन्होंने पत्रकारों को संक्षेप में बताया कि उनकी मां शुक्रवार को एजेंसी के सामने पेश होंगी। सूत्रों ने

बताया कि उनसे बैंक से जुड़े कुछ दस्तावेज लाने के लिए कहा गया था, हालांकि यह तुरंत पता नहीं चल सका कि उन्होंने वे दस्तावेज जमा किए या नहीं।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा, यह पूछताछ नगरपालिका भर्ती घोटाले से जुड़े धन के कथित लेनदेन की हमारी जांच का हिस्सा है। हम वित्तीय लेन-देन और संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में नगर निकाय भर्तियों में कथित अनियमितताओं की एजेंसी की जांच के तहत, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता और उनके परिवार के सदस्यों को कुछ दिन पहले समन जारी किए गए थे। ईडी का नोटिस मिलने के बाद टीएमसी विधायक ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे और जरूरत पड़ने पर उनकी पत्नी और बेटे भी एजेंसी के सामने पेश होंगे।

चालक दल सदस्य के बीमार पड़ने के बाद हैदराबाद में आवास व्यवस्था की समीक्षा कर रही ब्रिटिश एयरवेज

नई दिल्ली/भाषा। विमानन कंपनी ब्रिटिश एयरवेज चालक दल के एक सदस्य के बीमार पड़ने की खबरों के बाद हैदराबाद में अपने आवास व्यवस्था की समीक्षा कर रही है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। कंपनी हैदराबाद से लंदन के लिए रोजाना उड़ान संचालित करती है। हैदराबाद से लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे जा रही एक उड़ान के दौरान विमानन कंपनी के चालक दल के स्छसय के बीमार पड़ने की खबरें आई थीं। ब्रिटिश एयरवेज के एक प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को कहा, हमारे सहयोगियों का स्वास्थ्य और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। चालक दल के सदस्य के बीमार होने की खबरें सामने आने के बाद हम इस स्थान पर चालक दल के ठहरने की व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं।

प्रवक्ता ने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। सूत्रों ने बताया कि इस सप्ताह की शुरुआत में हैदराबाद से लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे जा रही उड़ान के दौरान एक पायलट की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्होंने कहा कि तय प्रक्रियाओं के अनुसार विमान सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचा और सामान्य रूप से उतरा। विमानन कंपनी दिल्ली, बेंगलूरु, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई से लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे के लिए सप्ताह में 63 उड़ानें संचालित करती है। हैदराबाद और चेन्नई से इसकी रोजाना उड़ानें हैं।

त्वरित अदालत बनाने की घोषणा प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों का समाधान नहीं : अरविंद केजरीवाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि पेपर लीक मामलों के लिए त्वरित अदालतें बनाने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की प्रदर्शनकारी छात्रों की मुख्य मांग को पूरा नहीं करती। केजरीवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स' पर एक वीडियो संदेश में कहा कि छात्रों ने यह मांग नहीं की थी।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने मोदी की सुबह की टिप्पणियों का ज़िक्र करते हुए कहा, ''आज सुबह प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि पेपर लीक मामलों के लिए त्वरित अदालतें बनाई जाएंगी। (लेकिन) धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का क्या हुआ?'' उन्होंने कहा कि देश में कई

मामलों के लिए पहले से ही त्वरित अदालतें हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने इन अदालतों की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाए। केजरीवाल ने कहा कि युवाओं के लिए अपने संदेश में मोदी ने सोमवार के विरोध-प्रदर्शन के दौरान छात्रों के घायल होने की घटनाओं का ज़िक्र नहीं किया।

मोदी ने पूर्वाह्न में कहा कि देश के युवाओं का कल्याण उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो कोई भी उनके (युवाओं के) भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ और प्रधान के इस्तीफ़े की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के नेतृत्व में हज़ारों छात्रों ने सोमवार को चलो संसद' मार्च आयोजित किया था। मार्च के दौरान, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे कई छात्र घायल हो गए। मार्च रोकने की कोशिश में 100 से ज़्यादा

सुविचार

मेहनत का कोई विकल्प नहीं। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है, जो कर्म में विश्वास रखते हैं। आज मेहनत करें, कल सफलता पाएँ।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

महफिल लूटने की होड़

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन में विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं ने कुछ ज्यादा ही तीखे तेवर दिखा दिए। उन्हें देखकर किसी को भ्रम हो सकता है कि धरती पर इनसे बड़ा छात्र-हितैषी कोई और नहीं है। हालांकि विरोध प्रदर्शन में जाना उनका अधिकार है। वे किसी के हक में आवाज उठाने के लिए आज़ाद हैं। ऐसे मौकों पर इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि जो दल आज खुद को सच्चे क्रांतिकारी की भूमिका में पेश करने को आमादा हैं, जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने छात्रों का कितना भला किया था? क्या उनके राज में पुलिस आम जनता पर रोजाना ही पुष्पवर्षा कर रही थी? क्या उन्होंने गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी को दूर कर दिया था? सीजेपी का 'प्रदर्शन' जिस दिशा में जा रहा है, उससे साफ पता चलता है कि यह कोई प्रदर्शन नहीं है। अब तक सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके इसके केंद्र में थे। जैसे-जैसे मामला तूल पकड़ता जा रहा था, विपक्षी दलों में इस बात को लेकर बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि कहीं ये दोनों ही मैदान फतह न कर लें! उनके मन में वर्ष 2011 की यादें जरूर ताजा हुई होंगी, जब अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन कर संप्रग सरकार की जड़ें हिला दी थीं। अरविंद केजरीवाल और उनके साथी उसी आंदोलन से निकले थे, जो मंच पर बड़े-बड़े भाषण देकर भ्रष्टाचार खत्म करने की कसमें खाया करते थे। बाद में, वे खुद भ्रष्टाचार, गुटबाजी, सार्वजनिक धन की बर्बादी समेत कई गंभीर आरोपों के लपेटे में आए और दिल्ली विधानसभा चुनाव बुरी तरह हारे। इस बार कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल फूंक-फूंककर कदम रख रहे हैं। वे नहीं चाहते कि सोनम वांगचुक या अभिजीत दीपके की शक्ल में फिर कोई 'केजरीवाल' प्रकट हो जाए। वे इस बात का जोखिम नहीं लेना चाहते कि दोबारा कोई आम आदमी पार्टी उभरे और वह उनकी जमीन पर कब्जा कर ले।

विपक्षी दलों के लिए यह प्रदर्शन महफिल लूटने की होड़ में बदल गया है। उनके कैमरों ने पोजिशन संभाल ली है। कुछ मिनटों के हंगामे के बाद, उनका आईटी विभाग सोशल मीडिया पर तस्वीरें फैलाकर ऐसा माहौल बनाने में एड़ी-चोटी का जोर लगा रहा है कि छात्रों के लिए अकेले हम फिक्रमंद हैं। इन तस्वीरों के जरिए आगामी चुनावों में वोटबैंक पक्का करने का जतन किया जाएगा। कांग्रेस को खटका है कि वह सपा और 'आप' से पीछे न रह जाए, इसलिए गुरुवार शाम होते-होते राहुल गांधी तीन बसों में इंडि गठबंधन के कई नेताओं को लेकर 'गांधी स्मृति' पहुंच गए। उन्होंने फुटेज लेने की पूरी कोशिश की। श्रेय लेने में कोई और बाज़ी न ले जाए, इसके लिए माहौल बनाया। पहले, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई थी, बाद में जाने दिया। 'आप' ने यह आरोप लगाकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है कि राहुल को प्रधानमंत्री आवास के बाहर इसलिए धरने की 'मौन स्वीकृति' मिली, ताकि 'आप' और सीजेपी को कमजोर दिखा सकें। वह कांग्रेस में भाजपा की बी टीम ढूंढ़ रही है। वैसे, सीजेपी वाले भी अपने एक रणनीतिकार को ढूंढ़ रहे थे, जो देशभर के युवाओं से जंतर-मंतर आने, 'संसद चलो मार्च' में शामिल होने की अपील कर खुद मशहूर फ़ास्ट फूड आउटलेट का बर्गर खाने में व्यस्त हो गए। प्रवक्ता पद से हटाए जाने के बाद विजेता दहिया समाचार चैनलों और सोशल मीडिया पर सीजेपी की पोल खोल रहे हैं। सीजेपी वाले इनकी पोल खोल रहे हैं। ये जनाब 'संसद चलो मार्च' के समय कहीं और तफ़रीह कर रहे थे। इन्हें देखकर युवाओं ने सवाल किए तो उन्हीं पर बरस पड़े। अंग्रेजी में धुआंधार प्रवचन देने लगे। जो जरा-सी भूख-प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके नारों पर आंखें मूंदकर विश्वास करना कितना उचित है? ऐसे लोग पूरी रात क्रांति की योजना बनाते हैं और पूरा दिन चद्दर ओढ़कर सोते हैं।

ट्वीटर टॉक

पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्दी और कड़ी सज़ा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है। हमने संबंधित अधिकारियों और अधिकारियों को इस बारे में सभी ज़रूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। यह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए हमारे कदमों की सीरीज़ को जारी रखता है।

-राजनाथ सिंह

पेपर लीक जैसी घटनाएं लाखों युवाओं की मेहनत, टैलेंट और सपनों पर चोट करती हैं। ऐसे अपराधों के खिलाफ फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के युवाओं के हितों की रक्षा करने और उनके उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित करने के पक्के इरादे को दिखाता है।

-दिया कुमारी

महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती पर, जिन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा के नारे से देशवासियों को आज़ादी के लिए जगाया, मैं उन्हें कोटि-कोटि नमन करता हूँ।

-सचिन पायलट

प्रेरक प्रसंग

गर्भ से ब्रह्मज्ञान तक

एक आयुर्वेद की कक्षा में एक छात्र ने अपने गुरु से प्रश्न किया कि गुरुदेव, मनुष्य को न तो अपने जन्म का पता चलता है और न ही अपनी मृत्यु का। फिर जीवन और मृत्यु का वास्तविक रहस्य क्या है? गुरु बोले, जैसे तृण-जलायुका (जोंक) घास के एक तिनके के अंतिम सिरे तक पहुंचकर पहले दूसरे तिनके को दृढ़ता से पकड़ती है और उसके बाद ही पहले तिनके को छोड़ती है, उसी प्रकार जीवात्मा भी अपने संचित कर्मों और वासनाओं के अनुसार अगले शरीर का आधार प्राप्त करती है। और वह पुराने शरीर से अपना संबंध समाप्त कर देती है। गुरु ने आगे समझाया कि नया शरीर प्राप्त करने की प्रक्रिया माता के गर्भ के माध्यम से होती है। गर्भ ही वह सेतु है जिसके द्वारा जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा पूर्ण करती है। गर्भ तम से ढक जाता है जिसके कारण उसके पहले जन्म की बातों का स्मृति नाश हो जाता है। इसलिए उसे पूर्वजन्म की बातें याद नहीं रहती। अगला शरीर उसको संचित कर्मों और वासनाओं के अनुसार अगला जन्म मिलता है। इसी कारण जीव बार-बार जन्म और मृत्यु के इस चक्र में जोंक की भांति एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करता रहता है।

सामयिक

विश्व में भारत के खिलाफ नैरेटिव गढ़ता बीबीसी

संजय सक्सेना

मोबाइल : 9454105568

यह आंदोलन मूल रूप से नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा के पेपर लीक और उसमें सुधार की जायज मांगों को लेकर जमीन पर उतरा था, लेकिन बीबीसी ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स और वीडियो पैकेज में इसे केवल एक परीक्षा प्रणाली या प्रशासनिक विफलता के रूप में नहीं दिखाया। बीबीसी की रिपोर्टिंग ने इसे सीधे पीएम मोदी की नीतियों और 12 साल के शासनकाल के खिलाफ एक सीधे राजनीतिक खतरे के रूप में पेश किया। बीबीसी के संवाददाताओं ने बार-बार यह नैरेटिव गढ़ा कि मोदी सरकार युवाओं की आवाज को दबा रही है और देश में प्रेस स्वतंत्रता व नागरिक स्वतंत्रता लगातार गिर रही है।

दुनिया भर में अपनी पत्रकारिता के कारण सुर्खियों में रहने वाला बीबीसी (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन) का विवादों से गहरा नाता रहा है। कई देश बीबीसी की खबरों को उसके 'एजेंडे' के रूप में देखते हैं। बीबीसी पर भारतीय राजनीति, समाज और नीति-निर्माण को प्रभावित करने के लिए एजेंडा-आधारित पत्रकारिता और नैरेटिव मैनिपुलेशन (कहानियों को तोड़ने-मरोड़ने) के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। आलोचकों, विचारकों और भारत सरकार के समर्थकों का मानना है कि बीबीसी अक्सर भारत की नकारात्मक छवि पेश करता है और संवेदनशील मुद्दों पर एकतरफा दृष्टिकोण अपनाकर असंतोष को भड़काता है। ऐसा ही कुछ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान भी देखने को मिल रहा है। बीबीसी की रिपोर्टिंग पर नज़र डालने से कुछ विशेष पैटर्न सामने आते हैं, जिनके जरिए खबरों को एक खास दिशा दी जाती है। भारत से जुड़ी खबरों में ऐसे शीर्षकों का चयन किया जाता है, जो सीधे तौर पर देश की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। जटिल सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को सरलीकृत करके सीधे तौर पर बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक के रूप में पेश किया जाना। बीबीसी का लोकल नैरेटिव को ग्लोबल एजेंडा बनाना भी अक्सर चिंताजनक नजर आता है। उसके द्वारा स्थानीय स्तर के आपराधिक मामलों को राष्ट्रीय राजनीति और सरकार की नीतियों से जोड़कर दिखाने के कई उदाहरण मौजूद हैं। बीबीसी द्वारा अपनी रिपोर्ट में केवल उन्हीं विचारकों, पत्रकारों या कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाता है, जो सरकार विरोधी रुख रखते हैं। बीबीसी की दखलअंदाजी और मैनिपुलेशन के कई उदाहरण मौजूद हैं।बीबीसी द्वारा 2023 में दो भागों में जारी की गई इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' डॉक्यूमेंट्री में 2002 के गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। इस डॉक्यूमेंट्री को ऐसे समय पर रिलीज किया गया, जब भारत जी-20 (जी-20) की अध्यक्षता संभाल रहा था और वैश्विक मंच पर अपनी छवि मजबूत कर रहा था। इसमें भारत की सर्वोच्च अदालत द्वारा गठित एसआईटी की उस जांच को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया, जिसने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी। दरअसल, बीबीसी का उद्देश्य कानूनी रूप से सुलझ चुके इस संवेदनशील और ध्रुवीकरण करने वाले मुद्दे को दोबारा हवा देकर देश में राजनीतिक अस्थिरता और असंतोष पैदा करना था। साल 2020-2021 में भारत सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान बीबीसी की कवरेज को बेहद एकतरफा माना गया। बीबीसी की ग्राउंड रिपोर्टर्स और डिजिटल आर्टिकल्स में मुख्य रूप से आंदोलनकारियों के पक्ष को ही सही ठहराया गया। इसमें लाल किले पर हुई हिंसा और पुलिसकर्मियों पर हुए हमलों को या तो बहुत कम दिखाया गया या उन्हें जायज ठहराने की कोशिश की गई। कानूनों के समर्थन में खड़े करोड़ों छोटे किसानों के दृष्टिकोण को बीबीसी ने अपनी मुख्यधारा की कहानियों में कोई जगह नहीं दी। इस कवरेज ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश दिया कि भारत सरकार किसानों का दमन कर रही है, जिससे भारत की लोकतांत्रिक साख को चोट पहुंची।

वर्ष 2020 में समान नागरिक संहिता यानी सीएए विरोधी प्रदर्शनों और उसके बाद फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के दौरान बीबीसी की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे। बीबीसी ने सीएए को एक मुस्लिम विरोधी कानून के रूप में प्रचारित किया, जबकि यह कानून केवल पड़ोसी देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए था, न कि किसी की नागरिकता छीनने के लिए। दिल्ली दंगों की रिपोर्टिंग में बीबीसी ने हिंसा को एकतरफा मुस्लिम विरोधी दंगे के रूप में पेश किया, जबकि दंगों में दोनों पक्षों (हिंदू और मुस्लिम) के लोग मारे गए थे और खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा व पुलिस हेड कांस्टेबल रतन लाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बीबीसी की इस तरह की रिपोर्टिंग ने देश के भीतर सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ाने और विदेशों में भारत की छवि को एक असहिष्णु देश के रूप में पेश करने का काम किया।194% से लेकर अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 3%0 के हटने तक, बीबीसी की कश्मीर नीति को लेकर भारत में हमेशा आक्रोश रहा। बीबीसी अपनी रिपोर्टों में कश्मीर को भारत प्रशासित कश्मीर लिखता रहा। अनुच्छेद 3%0 हटने के बाद बीबीसी ने घाटी में केवल तालाबंदी, विरोध और सेना की कथित ज्यादतियों को ही दिखाया। वहां आतंकवाद के खात्मे, विकास कार्यों, स्कूलों के खुलने और कश्मीरी पंडितों के दर्द को उसकी रिपोर्टिंग में हमेशा हाशिए पर रखा गया। उसकी यह रिपोर्टिंग वैश्विक स्तर पर कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने और पाकिस्तान के रुख को अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा गया। वर्ष 2021 में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान बीबीसी की कवरेज मानवीय संकट से ज्यादा राजनीतिक प्रहार पर केंद्रित थी। बीबीसी ने श्मशान घाटों और जलती हुई चिताओं की तस्वीरों को अत्यधिक ड्रोन कैमरों के जरिए ज़ूम करके दिखाया। जबकि पश्चिमी देशों (जैसे अमेरिका और यूके) में महामारी से भीषण मौतें होने के बावजूद वहां के मीडिया ने लाशों और कब्रिस्तानों की ऐसी डरावनी तस्वीरें नहीं दिखाईं। आपदा के समय इस तरह के दृश्य बार-बार दिखाकर बीबीसी ने देश के भीतर जनता में पैनिक (डर का माहौल) पैदा किया और सरकार की व्यवस्था को पूरी तरह से विफल दिखाने का प्रयास किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि बीबीसी का यह रवैया महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरे निहित स्वार्थ थे। संवेदनशील मुद्दों को भड़काना, तथ्यों को आधा-अधूरा पेश करना और भारत की नकारात्मक छवि को दुनिया के सामने बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना इसकी कार्यशैली का हिस्सा रहा है।

बीबीसी की रिपोर्टिंग पर नज़र डालने से कुछ विशेष पैटर्न सामने आते हैं, जिनके जरिए खबरों को एक खास दिशा दी जाती है। उसके द्वारा भारत से जुड़ी खबरों में ऐसे शीर्षकों का चयन किया जाता है, जो सीधे तौर पर देश की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। बीबीसी बेहद आसानी से जटिल सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को सरलीकृत करके सीधे तौर पर बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक के रूप में पेश करके देश में टकराव की स्थिति पैदा करने से चूकता नहीं है। इसी तरह से स्थानीय स्तर के आपराधिक मामलों को राष्ट्रीय राजनीति और सरकार की नीतियों से जोड़कर दिखाया जाता है। बीबीसी के ताजा एजेंडे की बात की जाए तो अबकी उसने भारत के कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन को शुरुआत से ही एक बड़े और सुनियोजित तरीके से कवर किया है। आलोचकों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एक डिजिटल मजाक या सैटायर (व्यंग्य) के रूप में शुरू हुए इस अभियान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोदी विरोधी नैरेटिव में बदलने के पीछे बीबीसी की रिपोर्टिंग का बड़ा हाथ रहा है। बीबीसी ने जिस तरह से इस आंदोलन को हवा दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उनकी सरकार के खिलाफ नैरेटिव तैयार किया, उसके मुख्य बिंदु और तरीके की बात की जाए तो उसके द्वारा कॉकरोच जनता पार्टी के डिजिटल व्यंग्य को वैश्विक जन-विद्रोह के रूप में प्रोजेक्ट करना बीबीसी की बड़ी चाल थी। शुरुआत में अभिजीत दिपके द्वारा बनाई गई कॉकरोच जनता पार्टी केवल एक मजाकिया सोशल मीडिया पेज था, जिसके सदस्यता मानदंडों में बेरोजगार होना, आलसी होना और प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालना शामिल था। बीबीसी ने अपनी रिपोर्टर्स में बार-बार इस बात पर जोर दिया कि सीजेपी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या भाजपा से भी आगे निकल गई है, जिससे वैश्विक स्तर पर यह संदेश गया कि मोदी सरकार अपनी लोकप्रियता पूरी तरह खो चुकी है।

यह आंदोलन मूल रूप से नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा के पेपर लीक और उसमें सुधार की जायज मांगों को लेकर जमीन पर उतरा था, लेकिन बीबीसी ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स और वीडियो पैकेज में इसे केवल एक परीक्षा प्रणाली या प्रशासनिक विफलता के रूप में नहीं दिखाया। बीबीसी की रिपोर्टिंग ने इसे सीधे पीएम मोदी की नीतियों और 12 साल के शासनकाल के खिलाफ एक सीधे राजनीतिक खतरे के रूप में पेश किया। बीबीसी के संवाददाताओं ने बार-बार यह नैरेटिव गढ़ा कि मोदी सरकार युवाओं की आवाज को दबा रही है और देश में प्रेस स्वतंत्रता व नागरिक स्वतंत्रता लगातार गिर रही है। 20 जुलाई 2026 को जब संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और दिल्ली पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुईं, तो कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। इसे बीबीसी ने अपनी हेडलाइंस और वीडियो में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को क्रूर और बर्बर क्रैकडाउन के रूप में बार-बार उछाला।

बीबीसी ने इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया या बहुत कम महत्व दिया कि इस हिंसा में 100 से अधिक पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। जलते हुए तंबू और आंसू गैस के दृश्यों को इस तरह दिखाया गया, जैसे कि भारत में कोई अलोकतांत्रिक शासन चल रहा हो। जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दल इस आंदोलन के समर्थन में आए और प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया, तो बीबीसी ने इसे सरकार के लिए बढ़ते दबाव और संकट के रूप में प्रचारित किया।

नजरिया

कोयले नहीं, अब हरित ऊर्जा से रोशन हो भारत

योगेश कुमार गोयल

मोबाइल : 9416740584.

थर्मल इंजीनियरिंग के महत्व और योगदान को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष 24 जुलाई को 'राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस' मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य थर्मल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाना और इसके महत्व को सार्वजनिक स्तर पर उजागर करना है। दरअसल थर्मल इंजीनियरिंग ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा प्रबंधन इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी होती है। थर्मल इंजीनियरिंग उन अवस्थाओं के अध्ययन और उपयोग को समझने में सहायक होती है, जहां ऊष्मा, ऊर्जा और उसकी व्यवस्था का विशेष महत्व होता है। थर्मल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही एक विशेष उप-विषय है, जो ऊष्मा ऊर्जा की गति और स्थानांतरण से संबंधित है। ऊर्जा को दो माध्यमों के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है अथवा ऊर्जा के अन्य रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है।

एक थर्मल इंजीनियर का कार्य यांत्रिक प्रणालियों का रखरखाव, निर्माण या मरम्मत करना है, जिसमें ऊर्जा के अन्य रूपों में ऊष्मा हस्तांतरण प्रक्रिया शामिल होती है। थर्मल इंजीनियर विश्लेषण करता है कि यांत्रिक ऊष्मा स्रोत विभिन्न भौतिक और औद्योगिक प्रणालियों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। घरों तथा गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले एयरकंडीशनर तथा रेफ्रिजरेटरों में थर्मल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है। थर्मल इंजीनियरिंग के जरिये इंजीनियर ऊष्मा को अलग-अलग माध्यमों में उपयोग करने के अलावा ऊष्मीय ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में भी परिवर्तित कर सकते हैं। थर्मल इंजीनियरिंग वास्तव में बंद या खुले वातावरण में वस्तुओं को गर्म या ठंडा रखने की प्रक्रिया है और थर्मल इंजीनियर ऊष्मीय ऊर्जा को केमिकल, मैकेनिकल या विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनें तैयार करते हैं, जिनके जरिये वे ऊष्मा को नियंत्रित करते हैं। हमारे घरों या दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली इसी ऊष्मीय ऊर्जा से बनती है और यह बिजली बनाने का काम करते हैं थर्मल पावर स्टेशन।

ऊष्मीय शक्ति संयंत्र या ताप विद्युत केन्द्र के नाम से भी जाने जाने वाले थर्मल पावर स्टेशन ऐसे विद्युत उत्पादन संयंत्र होते हैं, जिनमें प्रमुख टरबाइनें भाप से चलाई जाती हैं और यह भाप कोयला, गैस इत्यादि को जलाकर पानी को गर्म करके प्राप्त की जाती है। पानी गर्म करने के लिए ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जिससे उच्च दाब पर भाप बनती है और बिजली पैदा करने के लिए इसी भाप से टरबाइनें चलाई जाती हैं। थर्मल पावर स्टेशनों में ऊष्मीय ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित किया जाता है और इसके लिए भाप से चलने वाली टरबाइनों का इस्तेमाल किया जाता है। भाप बनाने के लिए पानी को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, जिसके लिए कोयला, सोलर हीट, न्यूक्लियर हीट, कचरा तथा बायो ईंधन उपयोग किया जाता है।

दुनिया के कई देशों में अभी भी बिजली पैदा करने के लिए भाप से चलने वाली टरबाइनों का उपयोग किया जाता है किन्तु पर्यावरणीय खतरों को देखते हुए अब धीरे-धीरे बिजली पैदा करने के लिए सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा के अन्य स्रोतों को ही महत्व दिया जाने लगा है। भारत में इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हजारों मेगावाट क्षमता की कुछ अत्याधुनिक मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू भी की गई हैं। हजारों मेगावाट के कुछ सोलर प्लांट पहले से ही ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दे भी रहे हैं। दरअसल थर्मल पावर स्टेशनों में भाप पैदा करने के लिए कोयला जलाने से पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचती है क्योंकि इस प्रक्रिया में निकलने वाली हानिकारक गैसें हवा में मिलकर पर्यावरण को बुरी तरह प्रदूषित करती हैं, साथ ही कोयला या अपशिष्ट जलाने के बाद बचने वाले अवशेषों के निबटारे की भी बड़ी चुनौती मौजूद रहती है।

हालांकि भारत में थर्मल पावर स्टेशनों में बिजली पैदा करने के लिए कोयले के अलावा ऊर्जा के अन्य स्रोतों का भी इस्तेमाल किया जाता है किन्तु अधिकांश बिजली कोयले के इस्तेमाल से ही पैदा होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोयले को जलाया जाना और इससे होने वाली गर्मी, पारे के प्रदूषण का मुख्य कारण है। विश्वभर में करीब चालीस फीसदी बिजली कोयले से प्राप्त होती है जबकि भारत में करीब साठ फीसदी बिजली कोयले से, सोलह फीसदी अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा बायो गैस से, चौदह फीसदी पानी से, आठ फीसदी गैस से, 1.8 फीसदी न्यूक्लियर ऊर्जा से तथा 0.3 फीसदी डीजल से पैदा होती है। वैसे बिजली पैदा करने के लिए भले ही ऊर्जा के किसी भी स्रोत का इस्तेमाल किया जाए, प्रत्येक थर्मल पावर प्लांट में इसके लिए बॉयलर का इस्तेमाल होता है, जिसमें ईंधन को जलाकर ऊष्मीय ऊर्जा पैदा की जाती है, जिससे पानी को गर्म कर भाप बनाई जाती है, जो टरबाइनों को चलाने में इस्तेमाल होती है।

वायु प्रदूषण आज दुनियाभर में एक बड़े स्वास्थ्य संकट के रूप में उभर रहा है और इस समस्या के लिए थर्मल पावर प्लांटों से निकलने वाला उत्सर्जन भी एक बड़ा कारण है। इस समस्या से निपटने के लिए एक दशक से भी अधिक समय से उत्सर्जन मानकों को पूरा करने और नए कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को रोककर अक्षय ऊर्जा की तरफ कदम बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इन उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करता रहा है किन्तु थर्मल पावर प्लांट के लिए उत्सर्जन मानकों को लागू करने का मामला वर्षों से अधर में लटका है। पर्यावरण पर कार्यरत कुछ संस्थाओं द्वारा निरंतर मांग की जा रही है कि पर्यावरण मंत्रालय उत्सर्जन मानकों का पालन कराते हुए थर्मल पावर प्लांटों को प्रदूषण के लिए उत्तरदायी बनाए और अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नए थर्मल पावर प्लांटों का निर्माण रोका जाए।

माना जा रहा है कि उत्सर्जन मानकों का पालन करने में देरी के चलते सालभर में 70 हजार से ज्यादा मौतें समय पूर्व हो रही हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यरत संस्था ग्रीनपीस के अनुसार यदि उत्सर्जन मानकों को समय से लागू किया जाता तो सल्फर डाईऑक्साइड में 48 फीसदी, नाइट्रोडन डाई ऑक्साइड में 48 फीसदी और पीएम उत्सर्जन में 40 फीसदी तक की कमी की जा सकती थी, जिससे समय पूर्व हो रही इन मौतों से बचा जा सकता था।

थर्मल पावर प्लांटों में बिजली बनाए जाने के लिए कोयला जलाने के दौरान उससे बनी राख का 10 फीसदी से भी अधिक हिस्सा चिमनियों के जरिये धुएं के साथ ही वातावरण में घुल जाता है, जो गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बनता है। बहरहाल, आज जिस प्रकार दुनियाभर में पर्यावरणीय खतरों के मद्देनजर थर्मल पावर प्लांटों में कोयले के इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोतों का उपयोग किया जा रहा है, ऐसे में भारत को भी कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट के बजाय क्लीन और ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहन देना चाहिए। समय के साथ अब जरूरत इसी बात की है कि हम अक्षय ऊर्जा की ओर तेजी से कदम बढ़ाएं और बिजली बनाने के लिए चरणबद्ध तरीके से ऊर्जा के इन्हीं सुरक्षित स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा दें।।

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- दक्षिण भारत राष्ट्रमत

मां के खेलने के तीन दशक बाद नीदरलैंड में भारत के लिए विश्व कप खेलेगा बेटा

नई दिल्ली/भाषा। प्रीतम रानी सिवाच ने नीदरलैंड में 1998 में विश्व कप खेला था तब यशदीप सिवाच का जन्म भी नहीं हुआ था। विधि का विधान है कि करीब तीन दशक बाद वह उसी देश में, उसी टूर्नामेंट में भारत के लिये पदार्पण करने जा रहे हैं। भारतीय हॉकी में यह श्रेय हासिल करने वाली मां-बेटे की यह पहली जोड़ी है। नीदरलैंड और बेल्जियम में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले विश्व कप में यशदीप भारतीय टीम का हिस्सा हैं और उनके इस टूर्नामेंट से काफी जज्बात जुड़े हैं।

मैनचेस्टर राष्ट्रमंडल खेल 2002 की स्वर्ण पदक विजेता टीम की सदस्य रही भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान प्रीतम रानी सिवाच के बेटे ने भाषा को दिये इंटरव्यू में कहा, ''जब मुझे विश्व कप टीम में चयन का पता चला तो सबसे पहले मैने अपनी मां को बताया। वह काफी भावुक थी क्योंकि उन्होंने भी 1998 में नीदरलैंड के यूट्रेक्ट में विश्व कप खेला था।'' 26 वर्ष के इस डिफेंडर ने कहा, ''मेरे लिये विश्व कप में उसी देश में भारत के लिये खेलना जहां मेरी मां भी खेल चुकी है, बहुत खास है।'' भारतीय महिला हॉकी टीम यूट्रेक्ट विश्व कप में बारहवें और आखिरी स्थान पर रही थी लेकिन प्रीतम ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ मैच में दो गोल दागे थे। कभी तैराकी के शौकीन रहे यशदीप बचपन से अपनी मां का वह एलबम देखते आये हैं जिसमें उनकी एक्शन पिक्चर, टूर्नामेंट के फोटो और टीम फोटो हैं और शायद वहीं से उनके भीतर भी हॉकी स्टिक थामने का शौक पैदा हुआ। माता पिता के साथ राष्ट्रीय चैम्पियनशिप और दिल्ली में 2010 विश्व कप उन्होंने देखा था।

यशदीप ने कहा, ''मम्मी ने मुझसे काफी अनुभव साझा किये हैं। उनके पास पूरी एलबम

है जिसमें एक्शन पिक्चर, टूर्नामेंटों के फोटो , साथी खिलाड़ियों के फोटो हैं। मैं बचपन से देखता आ रहा हूं। उनकी टीम से बात होती रहती है और मुझे सबसे मार्गदर्शन मिलता है।''

सिवाच परिवार के लिये यह विश्व कप काफी मायने रखता है और पोडियम पर रहकर अपनी मां और पिता का अधूरा सपना यशदीप पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ''सिवाच परिवार के लिये यह विश्व कप बहुत खास है। मैं अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहता हूं और अपनी बहन के लिये प्रेरणा बनना चाहता हूं।'' प्रीतम दिग्गज मिडफील्डर रही हैं और कनिका फॉरवर्ड खेलती हैं लेकिन यशदीप को गोल करने से ज्यादा बचाने में मजा आता है। उन्होंने कहा, ''मेरी मां और बहन के नाम ज्यादा गोल होंगे लेकिन मुझे फुटबॉल फैन होने के कारण गोल बचाने और गोल में सहायता करने में ज्यादा मजा आता है। इसके अलावा मेरी ट्रेनिंग बचपन में पापा ने कराई जो डिफेंडर थे।''

घरों में घुसा पानी

गुजरात के सूरत जिले में गुरुवार को भारी बारिश के बाद लिंबायत के मीठी खाड़ी इलाके में सड़कें जलमग्न हो गईं और घर पानी से घिर गए।

साइकल रैली

केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों (कॉमनवेल्थ गेम्स) से पहले ग्लासगो ग्रीन स्थित कॉलिन फाउंटेन से आयोजित साइकिल रैली में अन्य लोगों के साथ भाग लिया।

बांग्लादेश के राष्ट्रपति के जल्द इस्तीफा देने की संभावना: सूत्रों का दावा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

ढाका/भाषा। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के अपने कार्यकाल की समाप्ति से लगभग दो साल पहले ही जल्द इस्तीफा देने की संभावना है। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह दावा किया। शहाबुद्दीन को पिछली संसद द्वारा देश के सर्वोच्च पद के लिए निर्वाचित किया गया था और वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, जो जुलाई-अगस्त 2024 में हुए छात्रों के हिंसक आंदोलन के काफी समय बाद भी अपने संवैधानिक पद पर बने हुए हैं। छात्रों के आंदोलन के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी। इसके बाद हसीना भारत चली गई थीं और पांच अगस्त 2024 से वहीं रह रही हैं। प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के एक वरिष्ठ नेता ने पीटीआई' से कहा, उनके (शहाबुद्दीन) जल्द ही इस्तीफा देने की संभावना है। उन्होंने हालांकि इस संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दी। समाचार पत्र 'प्रोथोम आलो' ने एक उच्च पदस्थ सरकारी सूत्र के हवाले से कहा कि सरकार उन खबरों से नाराज है, जिनमें दावा किया गया था कि शहाबुद्दीन ने हाल में हसीना से दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश की थी। बीएनपी के एक वरिष्ठ नेता ने 'द डेली स्टार' से कहा कि शहाबुद्दीन और हसीना के बीच हाल में टेलीफोन पर हुई बातचीत उनके संभावित इस्तीफे का एकमात्र कारण नहीं है, इसके बजाय यह मुद्दा ''काफी जटिल'' है क्योंकि हसीना के स्वदेश लौटने की घोषणा के बाद बांग्लादेश का राजनीतिक परिदृश्य और अधिक संवेदनशील हो गया है। इस महीने की शुरुआत में, हसीना ने कहा था कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी। बांग्लादेश ने हसीना के स्वदेश लौटने की योजना का ''स्वागत'' किया था लेकिन यह भी कहा था कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना होगा। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार, यदि राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं तो नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक संसद के अध्यक्ष हाफिजुद्दीन अहमद अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे।

गंगा मां की बेटियां: इंदिरा कृष्णन ने बताया दुर्गावती का सफर

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेत्री इंदिरा कृष्णन टेलीविजन ने कई फिल्मों और टीवी शोज में अपनी अलग पहचान बनाई है। इन दिनों वह टीवी शो 'गंगा मां की बेटियां' में दुर्गावती का किरदार निभा रही हैं, जो मजबूत सोच रखने वाली और अपने फैसलों पर अडिग रहने वाली महिला है। अभिनेत्री का कहना है कि इस किरदार के जरिए उन्हें एक ऐसी महिला की कहानी दिखाने का मौका मिला, जो ताकत के साथ-साथ अपनी कमजोरियों और भावनाओं को भी स्वीकार करती है। इंदिरा कृष्णन ने अपने किरदार को लेकर बात करते हुए कहा, ''दुर्गावती कई परतों वाला किरदार है। इस भूमिका को निभाने के दौरान मुझे एक कलाकार के तौर पर कई अलग-अलग भावनाओं को समझने और पर्दे पर उतारने का मौका मिला।

चेन्नई के एक थिएटर के बाहर प्रशंसकों ने अभिनेता-राजनेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज के अवसर पर उनकी एक विशाल कट-आउट पर दूध चढ़ाकर जश्न मनाया।

छात्रों के समर्थन में उतरीं आलिया भट्ट

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट देश में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर अपनी आवाज उठाई है। वहीं अभिनेता और राजनेता कमल हासन ने भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने सरकार और व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बच्चों की परेशानियों को समय रहते सुना जाना चाहिए था। दरअसल, देश में परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। इसी बीच कई छात्र संगठन और समर्थक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर अब मनोरंजन जगत की कई हस्तियां भी प्रतिक्रिया दे रही हैं। आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नोट साझा करते हुए लिखा, ''पिछले कुछ दिनों ने मेरा दिल कई बार तोड़ा और फिर उम्मीद के साथ उसे जोड़ा। हर उस छात्र के पीछे एक सपना, परिवार की उम्मीद, वर्षों की मेहनत और त्याग की कहानी छिपी होती है। छात्र सिर्फ अपने लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, बल्कि वे उन लोगों की उम्मीदों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिन्होंने उनका साथ दिया है। छात्रों का साहस समाज के सामने यह सवाल रखता है कि क्या हम वास्तव में उन लोगों की बात सुन रहे हैं, जो देश का भविष्य संभालने वाले हैं।''

वहीं, अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने भी इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए देश की शिक्षा व्यवस्था की कमियों पर सवाल उठाए। कमल हासन ने कहा कि जब बच्चों की परेशानियों को समय रहते नहीं सुना जाता, तो हालात गंभीर हो जाते हैं।उन्होंने लिखा, ''हमें तब सुनना चाहिए था, जब एक बच्चा रोया था लेकिन हमने तब तक इंतजार किया, जब तक बहुत सारे बच्चों की आवाज खामोश नहीं हो गई।'' कमल हासन ने शिक्षा व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहा, ''ऐसी व्यवस्था, जहां पढ़ाई और सीखने की जगह सिर्फ कोचिंग का दबाव बढ़ जाए, जहां जिज्ञासा की जगह डर पैदा हो और जहां योग्यता की जगह गलत तरीके आगे आने लगें, वह व्यवस्था कमजोर हो जाती है। जब बच्चों को जवाब देने की जगह बैरिकेड और लाठियां मिलती हैं तो यह देश की विफलता है।''

कमल हासन ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से अपना अनशन खत्म करने की अपील भी की। उन्होंने लिखा, ''वांगचुक जी, आने वाले समय के लिए देश को आपके विवेक की जरूरत होगी। कृपया अपना अनशन खत्म करें। भारत के बच्चों, आप हमारे बीच के सबसे अच्छे इंसान हैं। आपने अपना कर्तव्य निभाया है। अब समय है कि देश आपके लिए अपना कर्तव्य निभाए।

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राजस्थान का गौरव बढ़ाया

लेखक-निर्देशक राधेश्याम पीपलवा की 'मोग आसुम' सर्वश्रेष्ठ कोंकणी फिल्म घोषित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुम्बई। विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित तथा भारत में सिनेमा के क्षेत्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माने जाने वाले 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (2024) में राजस्थान के लिए अत्यंत गर्व का क्षण आया है। राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी निवासी, लेखक, निर्माता एवं निर्देशक राधेश्याम पीपलवा की कोंकणी फीचर फिल्म मोग आसुम' को सर्वश्रेष्ठ कोंकणी फिल्म के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि राधेश्याम पीपलवा अब तक चार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र राजस्थानी फिल्मकार बन चुके हैं। वे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की राष्ट्रपति जूरी के सदस्य भी रह चुके हैं तथा उनकी फिल्मों को विश्वभर के विभिन्न प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में 70 से अधिक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं।

फिल्म के विषय पर अपने विचार साझा करते हुए पीपलवा ने कहा कि 'मोग आसुम' (अर्थात प्यार बना रहे) प्रेम, रिश्तों और मानवीय संवेदनाओं की एक अत्यंत मार्मिक और आत्मीय कहानी है। यह फिल्म न केवल कोंकणी भाषी समाज की समृद्ध संस्कृति और जीवन-मूल्यों को सशक्त रूप से प्रस्तुत करती है, बल्कि क्षेत्रीय सिनेमा को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान भी दिलाती है। करीब 500 से अधिक फिल्मों में से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जूरी ने 'मोग आसुम' का चयन किया है। शीघ्र ही राधेश्याम पीपलवा को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राधेश्याम पीपलवा और एंजेलो बरगांज़ा द्वारा लिखित एवं निर्देशित तथा राधेश्याम पीपलवा, शरद मित्तल और एंजेलो बरगांज़ा द्वारा निर्मित यह फिल्म अपनी विषय-वस्तु और प्रस्तुति के कारण समकालीन भारतीय सिनेमा में अलग पहचान रखती है।

'मोग आसुम' राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के साथ यह सिद्ध करती है कि संवेदनशील कहानी, सशक्त लेखन और ईमानदार सिनेमाई दृष्टि किसी भी क्षेत्रीय भाषा की फिल्म को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी विशिष्ट पहचान दिला सकती है। यह सम्मान न केवल राधेश्याम पीपलवा की व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि राजस्थान, कोंकणी सिनेमा और भारतीय क्षेत्रीय फिल्मों के लिए भी गर्व का विषय है।

अमिताभ बच्चन ने अस्पताल के अनुभव के जरिए बयां किया जिंदगी का कड़वा सच

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेता अमिताभ बच्चन अपने ब्लॉग के जरिए दर्शकों के बीच खास मौजूदगी रखते हैं। मेगास्टार ने मंगलवार को हॉस्पिटल में भर्ती होने, सर्जरी और आईसीयू के बारे में बात की। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसी स्थिति में इंसान पर शारीरिक और मानसिक रूप से गहरा असर पड़ता है। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने पर्सनल ब्लॉग पर लिखा कि डिस्चार्ज के बाद घर का सफर अक्सर इलाज से भी मुश्किल होता है। उन्होंने लिखा, अस्पताल में सर्जरी और आईसीयू में रहने के बाद, कुशल डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की देखरेख में इलाज पूरा होता है, फिर छुट्टी मिलती है और घर वापसी होती है, लेकिन घर लौटने के बाद का समय शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक रूप से सबसे कठिन होता है। आप एक सम्मानित चैंपियन होते हैं और फिर एक दिन हार आपके सामने आ जाती है। यह जिंदगी का सबसे मुश्किल समय हो सकता है। उन्होंने लिखा, कुछ लोग इस दौर का हिम्मत से सामना करते हैं, जबकि कुछ हार मान लेते हैं और संघर्ष करते रहते हैं, वे साहस बनाए रखते हैं। वे हमेशा चैंपियन बने रहते हैं। जो ऐसा नहीं कर पाते, वे अपनी पुरानी सफलताओं को याद करते

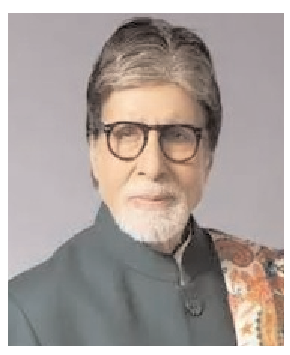

हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। यह हर व्यक्ति की अपनी निजी पसंद और फैसला होता है। दोनों में कुछ भी गलत नहीं है। स्वस्थ रहें, खुश रहें। हालांकि, मेगास्टार ने साफ तौर पर यह नहीं बताया है कि वह अपने बारे में बात कर रहे थे, या यह सिर्फ एक आम बात थी। अभिनेता फिलहाल, किसी भी तरह के गंभीर स्वास्थ्य समस्या ने नहीं जूझ रहे हैं।

एक्टर को आखिरी बार 'कल्कि 2898 एडी' में देखा गया था। इसमें अभिनेता ने 'अश्वत्थामा' का एक बेहद शक्तिशाली और ऐतिहासिक किरदार निभाया था। नाग अश्विन द्वारा निर्देशित इस डिस्टोपियन साइंस-फिक्शन फिल्म में पौराणिक कथाओं और भविष्य की दुनिया का अद्भुत मिश्रण दिखाया गया था, जिसमें अश्वत्थामा भगवान विष्णु के दसवें अवतार (कल्कि) की रक्षा करते हैं।

प्रश्न पत्र लीक होना गंभीर मुद्दा, प्रभावित लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं : सलमान खान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। अभिनेता सलमान खान ने प्रश्न पत्र लीक होने को एक गंभीर मुद्दा बताते हुए इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया है तथा कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के दौरान घायल हुए लोगों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। बॉलीवुड अभिनेता ने छात्रों के रुख की सराहना की और कहा कि उन्होंने अपने भविष्य तथा एक बेहतर, शिक्षित भारत के लिए कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने के प्रति समर्पण, ईमानदारी और उत्साह दिखाया है। अभिनेता ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, यह बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन था, पर यह देखकर बहुत दुख हुआ कि यह हिंसक आंदोलन में बदल गया।

चोटिल हुए छात्रों और उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। प्रश्न पत्र लीक होना बहुत गंभीर मुद्दा है और मुझे यह जानकर तथा देखकर खुशी है कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए हैं और उनके माता-पिता ने उनका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए

अभिनेता ने कहा, यह आंदोलन, यह प्रदर्शन, आगे बढ़ने का सही तरीका है और छात्रों ने इसे शांतिपूर्ण तरीके से किया है। यह पीढ़ी बेहद साहसी और बहादुर है। शिक्षा के प्रति समर्पित और प्रेरित यह पीढ़ी भारत को गौरवान्वित करेगी। उन्होंने लिखा, यह मुद्दा छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के बीच का है। इस पर राजनीति हावी नहीं होनी चाहिए। इसका श्रेय केवल हमारे देश के छात्रों को मिलना चाहिए और मुझे विश्वास है कि सरकार भी उन्हें पूरा सहयोग देगी तथा एक मजबूत शिक्षा व्यवस्था बनाएगी। यह सभी के लिए लाभ की स्थिति होगी। सकारात्मक फैसले की उम्मीद और प्रार्थना करता हूं।

नीट प्रश्नपत्र लीक होने के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन को फिल्म उद्योग के कई लोगों का समर्थन मिला है, जिनमें नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, शबाना आजमी, प्रकाश राज, राजकुमार राव, रेवती, टोविनो थॉमस और अनुराग कश्यप शामिल हैं।

आदिगौड़ के युवाओं ने 101 दिन तक बांटी छाछ

चेन्नई/दक्षिण भारत। यहां आदिगौड़ ब्राह्मण महासभा व आदिगौड़ समाज द्वारा सभी सदस्यों के उदार अर्थदान, स्वयंसेवकों के समर्पित श्रमदान तथा ट्रस्ट एवं सभा के शीर्ष अधिकारियों के प्रेरणादायक मार्गदर्शन से संचालित छाछ वितरण सेवा का 101 दिवसीय सफल अभियान आज संपन्न हुआ। भीषण गर्मी में हजारों राहगीरों तक शीतलता एवं सेवा का संदेश पहुँचाने वाला यह अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज की एकजुटता, सेवा-भाव और समर्पण का जीवंत उदाहरण रहा है। सभा सदस्य विष्णु एवं सोनू, जिनके अथक परिश्रम, निरंतर उपस्थिति और सेवा के प्रति समर्पण ने इस अभियान को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया। 101 दिनों की यह सेवा भले ही आज विराम ले रही हो, लेकिन समाज सेवा का यह संकल्प आगे भी निरंतर चलता रहेगा।

गुरु नानक महाविद्यालय में 'बैस्टिल डे' का आयोजन

चेन्नई/दक्षिण भारत । यहां गुरु नानक महाविद्यालय (स्वायत्तशासी) के बाबा दीप सिंह सभागार में उत्साहपूर्वक 'बैस्टिल डे' मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पॉन्डिचेरी में नियुक्त फ्रांस के महावाणिज्य दूतावास (उच्चायोग) (इंस्टिट्यूट फ्रैंकेस इंडिया) एवं दक्षिण भारत में वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक अटैची (विशेषज्ञ अधिकारी), ह्यूजेस बोइटो को आमंत्रित किया गया एवं उनका भव्य स्वागत सत्कार किया गया। 'इगालिटे टू एकता' थीम पर आयोजित इस समारोह में तमिल लोक कला, फ्रेंच फैशन वॉक, भरतनाट्यम तथा फ्रेंच थीम पर आधारित विज़ुअल आर्ट इंस्टॉलेशन व स्मारक शामिल थे। इन्हें विज़ुअल आर्ट्स विभाग एवं जी-टेक के सहयोग से तैयार किया गया था। साथ ही, यहाँ परस्पर संवादात्मक प्रतिक्रिया के लिए एक इंटरैक्टिव सिग्नेचर बोर्ड भी लगाया गया था। फ्रेंच विभाग ने समानता एवं सांस्कृतिक सद्भाव के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंच, तमिल, हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत भाषाओं में अंतर-महाविद्यालयीन भाषण एवं डिजिटल पोस्टर-निर्माण प्रतियोगिताएं भी आयोजित कीं। ह्यूजेस बोइटो ने महविद्यालय के उन रचनात्मक प्रयासों की सराहना की, जिनमें फ्रांसीसी आदर्शों व भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का मेल कराया गया, जिससे यह आयोजन अविस्मरणीय एवं सफल रहा।

इस समारोह में गुरु नानक महाविद्यालय के महाप्रबंधक एवं संवाददाता मंजीत सिंह नायर, प्रधानाचार्य डॉ. आर. एम. एषिलारासी, उपप्रधानाचार्य डॉ. पीवी कुमरगुरु, डीन अकादमिक, आमंत्रित विशिष्ट अतिथि एवं सदस्य, विभागाध्यक्ष, शिक्षक, मीडिया प्रमुख एवं कार्यकर्त्ता उपस्थित रहे।

जोधपुर एसोसिएशन के जेपीएल-5 क्रिकेट टूर्नामेंट में भंडारी ब्लास्टर्स ने जीता खिताब

चेन्नई/दक्षिण भारत। जोधपुर एसोसिएशन, चेन्नई द्वारा आयोजित जेपीएल-5 क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन पेरंबुर स्थित एसपीआर ग्राउंड में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। लीग एवं सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद खेले गए रोमांचक जेंट्स फाइनल में भंडारी ब्लास्टर्स ने केरवन्स स्टार्स को हराकर जेपीएल-5 का खिताब अपने नाम किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेन्द्र सिंघवी ने विजेता टीम भंडारी ब्लास्टर्स के मालिक एवं कप्तान मोहित भंडारी सहित पूरी टीम को शानदार प्रदर्शन एवं जेपीएल-5 का खिताब जीतने पर बधाई दी। रोमांचक टूर्नामेंट में मोहित दृढ़ा ने मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब हासिल किया,जबकि रोनित डाकलिया को पर्पल कैप एवं मोहित दृढ़ा को ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया।

महिला वर्ग में श्रेया सुपर किंग्स की श्रेया लुंकड़ ने खिताब अपने नाम किया, जबकि रचना लुंकड़ को विमेन ऑफ द टूर्नामेंट का सम्मान मिला। किड्स वर्ग में सुराणा सुरवीर टीम के मुन्नी सुराणा विजेता रहे तथा चरित बोहरा को किड्स ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया।टूर्नामेंट का शुभारंभ अध्यक्ष देवेन्द्र सिंघवी द्वारा सभी अतिथियों एवं खिलाड़ियों के स्वागत तथा गणेश वंदना के साथ किया गया। एसोसिएशन के सचिव पंकज मेहता ने बताया कि एसोसिएशन पिछले पाँच वर्षों से लगातार इस क्रिकेट टूर्नामेंट का सफल आयोजन कर युवाओं, महिलाओं एवं बच्चों को एक मंच पर जोड़ने का सराहनीय प्रयास कर रही है। जेपीएल-5 के चेयरमैन मोनिक रूनवाल एवं को-चेयरमैन प्रभात श्री श्रीमाल ने मुख्य प्रायोजकों का विशेष आभार व्यक्त किया।

संपन्नता नहीं, प्रसन्नता हैं जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि : आचार्य कुलबोधिसूरी

चेन्नई/दक्षिण भारत। यहां वेपेरी जैन संघ में विराजित आचार्य श्री कुलबोधिसूरिश्वरजी म. ने गुरुवार प्रातःकालीन प्रवचन में आत्मा के स्वरूप का विवेचन करते हुए कहा कि आत्मा के अनंतकालीन परिभ्रमण का मूल कारण सुखों की अपेक्षा और गुणों की उपेक्षा है। जिसे सुख प्रिय है वह मिथ्यात्वी है, जबकि जिसे गुण प्रिय हैं वही सम्यक्तव प्राप्त आत्मा है। यदि अनंत भवों तक क्षणिक सुखों के पीछे भटकने के स्थान पर एक ही भव गुणों की साधना में लगाया होता तो जीवन की दिशा ही बदल जाती। आचार्यश्री ने कहा कि पंच परमेष्ठि को सर्वोच्च स्थान उनके गुणों के कारण प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि पूजा, आराधना और जिनवाणी श्रवण का वास्तविक फल धन-संपत्ति नहीं, बल्कि आंतरिक प्रसन्नता है। उन्होंने कहा, सुख मनुष्य को संपन्न बनाता है, जबकि गुण उसे प्रसन्न बनाते हैं। आज की इक्कीसवीं सदी में संपन्नता से अधिक प्रसन्नता की आवश्यकता है। उन्होंने प्रेरित करते हुए कहा कि प्रसन्नता होगी तो संपन्नता स्वयं आकर्षित होगी, किंतु केवल संपन्नता से प्रसन्नता मिलना आवश्यक नहीं है।गौतम स्वामी, भगवान महावीर, सम्राट श्रेणिक तथा पुणिया श्रावक के प्रसंगों के माध्यम से आचार्यश्री ने स्पष्ट किया कि सच्चा वैभव बाहरी संपत्ति नहीं, बल्कि अंतःकरण की प्रसन्नता है।

प्रवचन के अंत में आचार्यश्री ने आगामी रविवार से प्रारंभ होने वाले युवा शिविरों की जानकारी दी। साथ ही चातुर्मास के दौरान बाल तपस्वियों के लिए न्यूनतम 50 बियासना आराधना कराने की घोषणा की। आगामी रविवार प्रातः गौतम किरण परिसर में मां-बाप को भूलना नहीं विषय पर सार्वजनिक प्रवचन आयोजित होगा।

बड़े पैमाने पर माल बुकिंग के साथ सम्पन्न हुआ दि इनर स्टोरी ट्रेड शो

■ 5 हजार से अधिक व्यापारियों ने किया दौरा, करोड़ों का हुआ व्यापार
■ 'मेक इन इंडिया की थीम' पर आधारित रहा किया' का यह आयोजन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। स्थानीय कर्नाटक इनरवियर एसोसिएशन (किया) के तत्वावधान में प्रिंसेस साइन में आयोजित तीन दिवसीय वार्षिक ट्रेड फेयर दि इनर स्टोरी का गुरुवार को सम्पन्न हुआ। इस फेयर में करीब 5 हजार से अधिक व्यापारियों ने भाग लिया और आगामी सीजन के लिए बड़े पैमाने पर माल की बुकिंग कराई। किया' के अध्यक्ष महावीर मेहता ने बताया कि 'मेक इन इंडिया' की अवधारणा पर आधारित इस मेले में करोड़ों रुपए के व्यापार अनुबंध किए गए हैं। गत वर्ष यह आंकड़ा लगभग 90 करोड़ रुपए रहा था, जिसे इस बार पार कर लिया गया है।

किया के उपाध्यक्ष अश्विन सेमलानी ने बताया कि यह पूरी तरह से मेक इन इंडिया' की थीम पर केंद्रित था, जिसमें 60 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे। उपाध्यक्ष व प्रदर्शनी समन्वयक गौरव शर्मा ने कहा कि पूरी टीम के बेहतर समन्वय और व्यापारियों के सहयोग से यह कार्यक्रम पूरी तरह सफल रहा। इस प्रदर्शनी में उत्कृष्ट योगदान देने वाली सभी कमेटियों के सदस्यों और प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। फेयर के टाइटल प्रायोजक 'टेक्नो स्पोर्ट्स एवं हीरा एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज' के जयंतीलाल जैन और दिनेश जैन विशेष रूप से उपस्थित थे। इसके अलावा मुख्य व अन्य प्रायोजकों का सम्मान किया गया।

प्रदर्शनी के दौरान व्यापारियों का उत्साह बढ़ाने के लिए आयोजित किए जा रहे लकी कूपन ड्रॉ में दूसरे दिन के प्रथम विजेता के रूप में बोम्मनहल्ली के बालाजी फैशन प्रिया करुणाकरन को रजत सिक्का भेंट कर सम्मानित किया।

कार्यक्रम में एसोसिएशन के सचिव कृष्णमूर्ति, कोषाध्यक्ष राजेश चोपड़ा, संयुक्त सचिव सूरज शर्मा, संयुक्त कोषाध्यक्ष विनोद चौहान व मूलसिंह राजपुरोहित, निवर्तमान अध्यक्ष दिलीप जैन सहित कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य अमित जैन, मनीष जैन, माधुराम खदाव, शैंकी जैन, भरत जैन, श्रीपाल मेहता, विक्रम दास, मिश्री लाल प्रजापत, घेवरलाल बोराना एवं अन्य सदस्यों ने ट्रेड फेयर की व्यवस्था संभाली। कार्यक्रम के अंत में सभी व्यापारियों ने अगले वर्ष नए उत्साह और नए अंदाज़ के साथ पुनः मिलने के वादे के साथ विदाई ली।

रजत एवं एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा छात्रवृत्ति वितरण

चेन्नई/दक्षिण भारत । राजस्थानी एसोसिएशन तमिलनाडु (रजत) एवं राजस्थानी एजुकेशनल ट्रस्ट तमिलनाडु की ओर से रजत सेंट्रल हाल, एगमोर में छात्रवृत्ति वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अरिगनर अन्ना जुलोजिकल पार्क वंडलूर के डिप्टी डाइरेक्टर मनीष मीणा थे। रजत के अध्यक्ष अजीत चोरड़िया, नामित अध्यक्ष विजय गोयल, जनरल सेक्रेटरी दिनेश कोठारी, कोषाध्यक्ष सुरेश संचेती एवं छात्रवृत्ति चेयरमैन प्रवीण टाटिया इस मौके पर उपस्थित थे। राजस्थानी एजुकेशनल ट्रस्ट तमिलनाडु के चेयरमैन सुभाषचंद रांका, कोषाध्यक्ष हेमंत दुगड़ भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

इस अवसर पर छात्रवृत्ति चेयरमैन प्रवीण टाटिया ने अपने संबोधन में कहा कि छात्रवृत्ति योजना के तहत इस वर्ष 490 छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इन छात्रों ने पिछले वर्ष की पढ़ाई में 83 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए थे। ट्रस्ट द्वारा प्रति वर्ष कॉलेज छात्रों 35 लाख रुपए से अधिक की राशि बतौर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 25,000 छात्रों को 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बतौर छात्रवृत्ति प्रदान की चुकी है उन्होंने बताया कि यह योजना पिछले 50 वर्षों से निरंतर चल रही है और शिक्षा को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। राजस्थानी एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत चोरडिया, ट्रस्ट के चेयरमैन सुभाषचंद रांका, सह-अध्यक्ष, समिति सदस्यों, राजेंद्र कुमार कोठारी (जनसंपर्क अधिकारी) ने स्वयंसेवकों का आभार व्यक्त किया जिनके सहयोग से यह परियोजना सफल रही। यह सहयोग छात्रों की आगे की पढ़ाई में मदद करेगा और भविष्य में जब वे कमाएंगे तो अन्य योग्य छात्रों की सहायता करेंगे।

एसीसीपीएल सीज़न-1 का में होगा बड़ा क्रिकेट महाकुंभ

चेन्नई। वर्ष 1996 में स्थापित अपना क्लब चेन्नई अपने 30वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में अपना क्लब क्रिकेट प्रीमियर लीग एसीसीपीएल-1 का आयोजन करने जा रहा है। अपना क्लब चेन्नई केवल सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी निरंतर कार्यरत है। क्लब द्वारा संचालित अपना क्लब चैरिटेबल क्लिनिक पिछले कई वर्षों से जरूरतमंद मरीजों को रियायती एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करा रहा है। यहाँ जनरल फिजिशियन, डेंटल, फिजियोथेरेपी, ईसीजी, लैब टेस्ट सहित विभिन्न चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अब तक 2.5 लाख से अधिक मरीज इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं। टूर्नामेंट के माध्यम से क्लब का उद्देश्य खेल के साथ-साथ समाज सेवा के इस मिशन को और अधिक मजबूत बनाना है। इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट में 16 टीमों, 240 खिलाड़ियों तथा 15-15 ओवर के रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे। समिति के अध्यक्ष ललित डांगरा, सचिव दीपक बंथिया, स्पोर्ट्स चेयरमैन : गौतम डागा, टूर्नामेंट डायरेक्टर गजेन्द्र बोहरा चीफ टूर्नामेंट कोऑर्डिनेटर कुलदीप चोरड़िया, स्पॉन्सरशिप चेयरमैन प्रवीण कोठारी, टूर्नामेंट कोऑर्डिनेटर संजय मुथा हैं।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

संत आगमन

तेरापंथ भवन गांधीनगर में चातुर्मास करने आई साध्वीश्री पावनप्रभाजी ने गुरुवार को जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (जीतो)नॉर्थ चैप्टर के गांधीनगर में बने नए कार्यालय का अवलोकन किया। नार्थ के अध्यक्ष विमल कटारिया एवं अन्य ने साध्वीश्री को नए कार्यालय की जानकारी दी। साध्वीश्री ने कहा कि जीतो का यह नवीन कार्यालय केवल एक भवन नहीं, बल्कि समाज के विकास, संस्कार, सहयोग और सकारात्मक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बने। कटारिया ने साध्वीश्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। रमेश बोहरा ने कहा कि जीतो कार्यालय में साधु वर्ग से साध्वीश्री का प्रथम आगमन हुआ है जो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है।

सिगा फेयर-2026 का तीन दिवसीय आयोजन 28 से

150 से अधिक ब्रांड करेंगे अपने उत्पादों का प्रदर्शन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

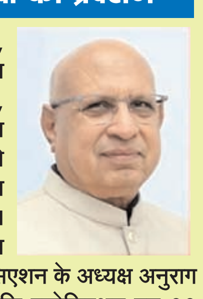

बेंगलूरु। दक्षिण भारत के गारमेंट एवं फैशन उद्योग के एक प्रतिष्ठित साउथ इंडिया गारमेन्ट एसोसिएशन के तत्वावधान में इस वर्ष भी 28 जुलाई से तीन दिवसीय 31वां 'सिगा फेयर - 2026' का आयोजन पैलेस ग्राउंड के प्रिंसेस श्राइन सभागार में होने जा रहा है। गारमेंट बाजार के बहुप्रतीक्षित इस ट्रेड फेयर में देशभर के 150 से अधिक प्रतिष्ठित गारमेंट एवं फैशन ब्राण्डस अपनी नवीनतम कलेक्शन और आगामी सीजन के ट्रेंडस के अनुसार उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। इस फेयर में महिला, पुरुष वर्ग सहित किड्स वेयर के साथ साथ पारम्परिक विवाह, केजुअल व फार्मल्स, डेनिक, वेस्टर्न, लाउंज, विंटर वियर की विस्तृत रेंज प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा गारमेन्ट उद्योग से जुड़े साफ्टवेयर, एकाउटिंग सिस्टम, उपकरण, मशीन व कच्चे माल से संबंधित स्टाल भी लगाए जाएंगे। साउथ इंडिया गारमेन्टस एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग सिंगला ने कहा कि एसोसिएशन गत 30 वर्षों से इस ट्रेड फेयर का आयोजन करता आ रहा है। यह ट्रेड फेयर केवल एक प्रदर्शनी नहीं अपितु भारतीय गारमेंट उद्योग के लिए बिजनेस ग्रोथ नेटवर्किंग और नए अवसरों का सशक्त प्लेटफार्म सिद्ध होता है। इस फेयर में गारमेन्ट निर्माताओं, वितरकों, रिटेलर्स व संबंधित जनों को व्यापार के नए ट्रेंड की जानकारी देता है और नए बाजार का निर्माण करता है। व्यापारियों को नए उत्पादों व उभरते फैशन ट्रेंडस के प्रदर्शन के लिए भी यह ट्रेड फेयर एक अच्छा विकल्प बनकर उभरता है ।

हर सनातनी की सांसों में बसते हैं श्री राम : योगी

गोरखपुर/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि सनातन परंपरा को मानने वाले हर व्यक्ति की हर सांस में भगवान श्री राम बसते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम ही ऐसा है जिससे हर कोई अपनापन महसूस करता है। आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में आयोजित सात दिवसीय 'श्री राम कथा' के उद्घाटन समारोह में मौजूद भक्तों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, ''भक्ति के बिना जीवन केवल अंधेरे से भरा होता है। भक्ति के बिना जीवन में सिर्फ अराजकता और अज्ञानता होती है।

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.